SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Let the Government respond ...*(Interruptions)*...

श्री मूल चन्द मीणा (राजस्थान) : मैडम, लॉ मिनिस्टर हैं। ...**(व्यवधान)**...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now, he is responding ...*(Interruptions)*... Please sit down...*(Interruptions)*...

THE MINISTER OF LAW AND JUSTICE AND MINISTER OF COMMERCE AND INDUSTRY (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, hon. Kapil Sibal and the hon. Leader of the Opposition have raised the issue with regard to a criminal case pending in some courts of U.P. Let me just mention that the case, as Mr. Sibal has mentioned, pertains to a chargesheet which was filed in 1993. The Government, whether in 1998 or in 1999, have, at no stage, interfered in the process of CBI in the conduct of this case. The Government have no intention of interfering in that matter. It is how the case goes on or how a criminal trial goes on is not a matter in which the Government interfere because the rights of the prosecution are involved, case of the prosecution is involved and rights of the accused are involved. The Government, in this matter, does not intend, in any way, to interfere...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Mr. Ramaswamy ...*(Interruptions)*... Now, the Government has responded ...*(Interruptions)*... No, please, take your seats ...*(Interruptions)*...

SHRI KAPIL SIBAL: Madam, the Government is denigrating the court ...*(Interruptions)*...

DR. MANMOHAN SINGH: Madam, this reply is, totally unacceptable and unsatisfactory. As a mark of our protest, we are walking out.

प्रो. रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : हम भी असन्तुष्ट हैं, इसलिए हम भी वॉक आउट करते हैं।

(At this stage some hon. Members left the Chamber)

MOTION OF THANKS ON PRESIDENT'S ADDRESS - (Contd.)

SHRI CHO S. RAMASWAMY (Nominated): Madam Deputy Chairman, I rise to make my submissions on just one issue, among the various issues, mentioned in President's Address. The hon. President has

spoken about the continued incidents of cross-border terrorism. The Foreign Minister, the Home Minister and some of the diplomats have also spoken about this menace. Madam, India has been a victim of cross-border terrorism for more than a decade and we have lost more than 50,000 lives. And, what do we propose to do? The hon. President says, 'our position remains unchanged. We are willing to resume bilateral dialogue with Pakistan as soon as cross-border terrorism ends.' That means, we will not talk with our neighbour till cross-border terrorism stops. This is the most powerful ultimatum that has been issued by us. Of course, we have also said that we will not play cricket with you on your land. Madam, 50,000 innocent lives have been lost, temples were attacked, militants are trained and some are exported to our land. Lakhs of people are displaced. The security men lost their lives. The security guards in this Parliament laid down their lives and how do we retaliate? We retaliate by saying, "We will not play cricket with you on your land!" The hon. President has referred to the deployment of our troops along the international border. He has claimed that the Government has achieved its purpose by showing our firmness and self-restraint in dealing with our hostile neighbour. Simultaneous exhibition of firmness and restraint! What does this mean? Firmed restraint or restrained firmness? I do not know. And, what has been the result of this firmness and self-restraint? Has there been no terrorist attack? Even Bangladesh has become a heaven for terrorists. Its gives space to the militants, and to the ISI to establish its links with the militants. This is the result of our restrained firmness! What are you going to do? Perhaps, we will say that we will not play cricket with Bangladesh on their land. The most ominous result of all this has been that our nation appears to have concluded that we have to live with cross-border terrorism from Pakistan, aided and abetted by Bangladesh; and, that we have no way out of it. This is, indeed, a suicidal attitude for any nation to adopt. Why is this paralysis of character? Are we afraid of a nuclear attack from our neighbour? Do we believe that Pakistan will not venture to launch a nuclear attack for the fear of being eliminated out of existence? Or, do we consider our Defence Minister's confident assertion, in this regard, as mere bravado? The world over, nuclear weapons are proclaimed to be deterrents. Very true. True, indeed. But as far as our country is concerned, our nuclear weapons have become a deterrent for us, by us and of us. We are, indeed, fast becoming the mother of all soft nations. Or, is the Government driven to dithering in by the propaganda of perversive secularism, which declares all talks of confrontation with Pakistan as jingoism, and condemns all efforts

at educating the people about the menace of cross-border terrorism as communalism? There are only two ways to get out of this miserable situation. We can invite mediation by a third country, and get prepared to make concessions, to lose territory, also, perhaps to lose face, and buy peace. Or, the other way is, adopt the pro-active attitude, advocated by the Home Minister, once upon a time -- a policy, that would involve hot pursuit; a policy that may lead to an open conflict. We have had enough of the talks like 'There is a limit to our patience.' Let us announce that our patience has, indeed, reached its limit. And, let the die be cast in the hope that the Government would decide to buy peace at any cost, even at the cost of territory and sovereignty; or, would take a more honourable course, and would take the risk of intense conflict to establish permanent peace.

Madam, I support the Motion of Thanks on the President's Address. Having deployed myself in this debate to show my firmness, now I strategically re-deploy myself in my seat to show my self-restraint. Thank you.

उपसभापति : श्री लालू प्रसाद यादव। आपको हम बता दें, आपके 23 मिनट हैं।

श्री लालू प्रसाद (बिहार) : महोदया, बीच में अगर आप ही छेड़छाड़ करिएगा तो दिक्कत होगी।

उपसभापति : हम छेड़छाड़ नहीं करते। कोई दूसरा करे तो हमें मालूम नहीं।

श्री लालू प्रसाद : सीट का काम है सिर्फ सिर हिलाते रहना।

उपसभापति : अब हमें आपसे सीखना पड़ेगा कि कैसे चेयर चलाते हैं?

श्री लालू प्रसाद : महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी का अभिभाषण हमने देखा है, जब भी जो भी हमें समय मिला है। दो दो राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को देखने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि मौजूदा जो राष्ट्रपति जी हैं, जिनसे सरकार की नीति और पालिसी का उल्लेख कराया गया, दोनों अभिभाषण हमारे पास हैं नारायणन साहब का वर्ष 2002 का और यह अभी 2003 का, इन दोनों में काफी समानता है। एक ही तरह की असत्य बातों को दो राष्ट्रपति महोदयों से पढ़वाया गया। यह बात मैं जिम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ। ...(व्यवधान)... महोदया, राष्ट्रपति जी से यह गलत काम कराया गया है। इस बात का मुझे खेद है। महोदया, शुरु से ही हम लोग देश को लगातार यह बात बताते रहे हैं कि मौजूदा सरकार बहुत जल्दी जाने वाली है, इनसे कोई आशा करना या देश के लोगों द्वारा कोई उम्मीद करना अपने आपको धोखे में डालने के बराबर है। महोदया, विगत लोक सभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी तो एक मुखौटा थी, इसके पीछे संघ परिवार, तोगड़िया, विश्व हिन्दू परिषद या ऐसे तथाकथित लोग हैं जो कल साधु-

संतो के नाम पर नकली लोग यहां पर जुटे थे। मैं कहना चाहता हूं कि इस पार्टी की इस देश के प्रति और गरीबों तथा किसानो के प्रति न कोई दिशा है, न कोई सोच है, इनके जहन मे साम्प्रदायिकता कूट-कूट कर भरी हुई है। साम्प्रदायिकता इस देश के लिए सबसे बड़ी और घातक बात है और इसके कारण आज देश की स्थिति बद से बदतर हो गई है। देश के अंदर से लेकर सीमा तक जो हालात पैदा हुए हैं, उनके कारण आज देश टूट के कगार पर खड़ा है।

महोदया, भारत के संविधान का मेंडेट है, संविधान का यह एक मान्य सिद्धान्त है और हमारे संविधान मे है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा। इस भाषण मे भी एक जगह कहा गया है कि यह सरकार पंथ-निरपेक्ष है। यह कैसी पंथ-निरपेक्ष सरकार है? जिस सरकार के गृह मंत्री, शिक्षा मंत्री और अनेकों मंत्री बाबरी मस्जिद को गिराने मे दागदार हो, वह अपने को पंथ-निरपेक्ष कहते हैं ! ये सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की दुहाई देते हैं, जबकि इस देश के लोगो को हिन्दुत्व का नया पाठ पढ़ाया जा रहा है। महोदया, आज शून्यकाल शुरु होते ही हमने सभापति जी से जानना चाहा था कि रायबरेली मे श्री लाल कृष्ण आडवाणी और उनके साथियो पर बाबरी मस्जिद गिराने के सवाल पर सी.बी.आई. न्यायालय ने इजाजत मांगने का काम किया है, हमे बताया जाए कि इसका स्टेटस क्या है। सभापति जी ने कहा कि यह आपको और सदन को बता दिया जाएगा। जिस देश के होम मिनिस्टर, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी हो और केन्द्रीय मंत्रि-मंडल मे बैठे लोगों पर बाबरी मस्जिद गिराने का इल्जाम लग रहा हो, यह सरकार पंथ-निरपेक्ष कैसे हो सकती है? महोदया, हमारे दल की और हमारी मान्यता रही है कि अगर हम मस्जिद को गिराते हैं तो हमारा मंदिर सुरक्षित नही रहेगा। मस्जिद गिराते हैं तो मंदिर सुरक्षित नहीं, गिरिजाघर और गुरुद्वारा सुरक्षित नही। महोदया, मुझे तकलीफ है कि आज वाजपेयी जी की सरकार के समय मे न तो मस्जिद सुरक्षित है, न मंदिर सुरक्षित है, न गिरिजाघर सुरक्षित है, न गुरुद्वारा सुरक्षित है, न संसद सुरक्षित रही है और न ही सीमा पर सुरक्षा है। ये लगातार आतंकवाद की बात करते हैं, लेकिन हमको देखना पड़ेगा, राष्ट्र को देखना पड़ेगा कि साम्प्रदायिकता की गोद से, साम्प्रदायिकता के आंचल से आतंकवाद में इजाफा हुआ है।

महोदया, मुझे अफसोस है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में एक जगह भी गुजरात मे गोधरा मे जो कुछ हुआ, उसका एक जगह भी जिक्र नहीं है। देश को आज तक उस लिस्ट के बारे मे कुछ पता नही है -- वे कौन से पैसेंजर थे, किनके बेटे थे, जो लोग मारे गए? महोदया, पोटा कानून बनाना और उसका उपयोग करना यह बताता है कि सिर्फ माइनॉरिटी के लोग ही नहीं, झारखंड राज्य में, जो हमसे अलग हुआ है, 3200 आदमियों पर पोटा का कानून लागू किया गया है। 12 साल के बच्चे पर, ट्राईबल लोगों पर POTA लागू किया गया और 80 साल के बूढ़े पर भी POTA लागू किया गया।

महोदया, एक जगह भी भ्रष्टाचार मिटाने का जिक्र नही है। भाजपा ने अपने मैनीफैस्टो में कहा था कि वे भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाएंगे। लेकिन इनके पोर-पोर, इंच-इंच में भ्रष्टाचार है। यह दुनिया ने सुना नहीं, बल्कि अपनी आंखो से देखा कि किस तरह से हमारे रक्षा के सौदों में भ्रष्टाचार किया गया। हमारे देश की रक्षा की बागडोर जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति को दी गई, जिस समाजवादी को दी गई, डा. जॉर्ज फर्नान्डीज को दी गई, उनके निवास स्थान पर रक्षा का सौदा हो रहा है, इस तरह का घपला हो रहा है। देश यह जानना चाहता है कि क्या यही आपकी नैतिकता है?

आपने कहा कि बिहार मे लोग चारा खा जाते हैं, लालू चारा खा गया। आपने गलत आरोप लगाया। पांच-सात साल से उछल-उछलकर, एड़ियों पर कूद-कूदकर देश के प्रधानमंत्री बोलते रहे कि लोग बिहार मे चारा खा जाते हैं। इनके भ्रष्टाचार का आलम इतना आगे बढ़ा कि दुनिया ने उसे अपनी आंखो से देखा। जिस मंत्री के कारण संसद नहीं चली, देश भर की पत्र-पत्रिकाओ मे, दुनिया भर मे हमारी साख गिरी, उस मंत्री को हटाया गया। श्री बंगारू लक्ष्मण इनकी पार्टी के अध्यक्ष थे। पार्टी के अध्यक्ष नोट गिनते हुए पाए गए। वे दलित थे, इसलिए वे निकाल दिए गए। लेकिन जॉर्ज फर्नान्डीज को फिर यहां बिठा दिया गया। भारत के इतिहास में, संसद के इतिहास मे हमने ऐसा कभी नही देखा कि कोई ऐसा मंत्री हो जो चुपचाप बैठा रहे और उससे कोई प्रश्न न करे।

महोदया, मैंने रात को टी.वी. पर देखा कि अफसरो के खिलाफ कार्यवाही हुई लेकिन इस मंत्री के खिलाफ कोई कार्यवाही नही हुई। इन्हे क्यो दोबारा लिया गया? यह इतना बड़ा स्कैंडल हुआ, इतना बड़ा घोटाला हुआ। सबसे बढ़कर तो यह कफन घोटाला हुआ। यह कफन तक खा गया। कफनचोर आज गद्दी पर बैठा हुआ है और दुनिया मे भारत का नाम नीचे जा रहा है। तहलका मामले से लेकर चारो तरफ UTI घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, यह तो घोटालेबाजो की सरकार है।

महोदया, अब चूंकि चुनाव आ रहा है, इसलिए यह हिंदुत्व का पाठ पढ़ाया जा रहा है। एक तरफ जब आप आतंकवाद के खिलाफ और माईनॉरिटी के ऊपर POTA लगाने की बात करते हो तो आपने इन सांप्रदायिक ताकतो के ऊपर POTA क्यों नहीं लगाया? आपने तोगड़िया पर POTA क्यों नही लगाया? आपने सिंघल पर POTA क्यो नही लगाया? आपने रामचन्द्र परमहंस पर POTA क्यों नहीं लगाया? महोदया, रामचन्द्र परमहंस के बारे में हमने पता किया। मैं हैरान था। लोग बोलते थे कि यह तुम्हारा छपरा का ही आदमी है, बिहार का आदमी है। हमको उनकी बोली से लगता था कि जरूर यह छपरा का आदमी है। हमने रात को पता किया ...**(व्यवधान)**... मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं, आप गुमराह मत करिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल (उत्तर प्रदेश) : मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं। लेकिन यहां प्रथा यह है कि ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखण्ड) : महोदया, मेरा एक व्यवस्था का सवाल है। आप व्यवस्था दे कि सदन में संसदीय भाषा का प्रयोग किस तरह से होगा। दूसरी बात यह है कि जो लोग अपने बचाव मे इस सदन में उपस्थित नहीं हो सकते, ऐसे लोगों का नाम यहां लेना, क्या यह उचित है? क्या यह संसदीय परंपरा के अनुकूल है? मैं इस पर आपकी रूलिंग चाहता हूं।

उपसभापति : लालू जी, हमारी परम्पराएं ऐसी हैं, मैंने रूल नही बनाए हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : परम्पराएं तोड़ने आए हैं हम लोग। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : हमने नहीं बनाई हैं। ...**(व्यवधान)**... एक मिनट।

श्री लालू प्रसाद : क्या परम्पराएं रही हैं? क्या यहां बदमाशो का नाम नही लिया जाए? क्या यह परम्परा है कि हाऊस मे ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : लालू जी, मुझे आपसे इस पर कोई लड़ाई-झगडा नही करना है। जो परम्पराएं हैं वह मैं फॉलो कर रही हूं, जो 50 साल से कायम हैं। 50 साल के जनतंत्र पर कार्यक्रम आपने अभी मनाया। हम उन्हीं को कायम रखने की कोशिश कर रहे है।

श्री लालू प्रसाद : इसी स्टेटस को तोड़ने वाला हमारा दल है। आपके स्टेटस की वजह से देश का नाश हो रहा है। नाश हो रहा है, तथा कहा जाता है कि चुप रहो। चुप रहो, मत बोलो, यह संसद है। संसद को डिफेम किया तथा वहां संघ परिवार और विश्व हिन्दू परिषद मे एक भी सही साधु उसमे नही था। अगर आपने कल देखा होगा कि वे गांजा पी रहे थे ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : मैडम्, यह क्या हो रहा है ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : वह नाम नही ले रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : वह नाम नही ले रहे हैं लेकिन जिस तरह से संसद में ...**(व्यवधान)**... मैडम्, मेरा व्यवस्था का सवाल है। जो इस सदन के कानून को तोड़ने के लिए आए हैं वह क्या इस सदन के सदस्य रह सकते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : महोदया, हमने टी.वी. पर देखा है उनको गांजा पीते हुए। चिलम पकड़े हुए हमने टी.वी. पर देखा है। उसमे विदेशी महिलाएं भी थी जो कहीं से साधु बन कर आई थी। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदया, जो संसदीय प्रणाली को अपमानित कर रहे हैं वह इस सदन के सदस्य नही रह सकते? ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : अहलुवालिया जी, बैठिए। लालू जी, ऐसा है कि अगर आप नए कानून बनाएंगे तो हम उस पर चलेगे। ...**(व्यवधान)**... अब आप बैठिए न। ...**(व्यवधान)**...आप बैठिए।

श्री लालू प्रसाद : हमने क्या खराब कहा है। क्या सही साधु गांजा पीते हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे (बिहार) : मैडम,

THE DEPUTY CHAIRMAN: I am talking to a Member who is on his legs. Please do not interrupt. लालू जी, हम कोई आपको मना नही कर रहे हैं। लेकिन जो इसकी परम्पराएं बनी हुई हैं उसी पर चलने के लिए आपको कह रहे हैं। आप चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, आप बहुत अनुभवी हैं, हमसे ज्यादा अनुभवी हैं। मगर हम तो कानून पर चलने की बात करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है, उसके अंदर-अंदर आप बोलिए।

श्री लालू प्रसाद : हमने जेल मे कानून की डिग्री ली है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभापति : हम नही कह रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : महोदया, मैं बता रहा हूं। इस देश मे कोई भी संवैधानिक संस्था, हमारी न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट यह अंतिम अदालत है। कल हमने देखा, दुनिया ने देखा, सब लोगो ने देखा कि किस तरह से मोदी जी, तोगड़िया और संघ परिवार के लोग भड़काऊ भाषण दे रहे थे ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मैडम, व्यवस्था देने की कृपा करे। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : महोदया, सुप्रीम कोर्ट को बाध्य होकर के इन लोगो को नोटिस देना पड़ा। यह आप समझिए कि तोगड़िया, विश्व हिन्दू परिषद, अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी अलग-अलग हैं ऐसी बात नही है। सब का मुंह मिला हुआ है। एक जगहे ये जुटते हैं। जब एन.डी.ए. का कोई पार्टनर आता है -चन्द्रबाबू आते हैं तब यह जोड़ी मिल जाती है और बोलते हैं कि हमने ऐसा नही कहा, यह नहीं कहा है। इस तरह से देश मे संघ परिवार को और तथाकथित विश्व हिन्दू परिषद को पूरा जहर, साम्प्रदायिकता, साम्प्रदायिक उन्माद फैलाने की इजाजत दी जा रही है। मैं मानता हूं और मैं इस गवर्नमेंट को चार्ज करता हूं और मुझे खेद है कि एक शब्द का भी जिक्र नहीं किया। जो अफसरो ने दिया, हर विभाग से मंगा लिया, इसमें अपनी उपलब्धियां बताते हैं, इसमे कोई उपलब्धि है ही नही। महोदया, इस उस बात को गिना दिया गया, निवेश की बात कह दी गई, बिजली की बात कह दी गई, यह बात कह दी गई, वह बात कह दी गई। ग़रीबी रेखा के नीचे इतने लोग हैं, ये ऊपर आना चाहते हैं, ये उन्हे आने नही देना चाहते हैं। महोदया, इनका कार्यकाल अब समाप्त हो रहा है।

महोदया, तथाकथित साधु-संत यहां पर हरिद्वार से नहीं आये थे, किसी भी पीठ का शंकराचार्य इसमे नही आया, कृष्ण मंदिर से कोई संत यहां पर नहीं आया। कौन आया? महोदया, देखा गया होगा, त्रिशूल लेकर आया। यहां पर त्रिशूल बांटे जा रहे हैं। गांव मे रहने वाले लोग जो ब्रह्मचारी बने हुए हैं, नकली ब्रह्मचारी, लाचार ब्रह्मचारी, ये लोग बैठे हुए थे, ये लोग यहां पर आये थे। महोदया, एक आदमी की हमारे गांव में शादी नही हुई। उसे कोई पूछता ही नही था। किसी ने पूछा भाई क्यो तुम्हारी इतनी उम्र हो गई तो कहता है कि भाई हम तो ब्रह्मचारी हो गए हैं। अरे, तुम्हे तो किसी ने पूछा ही नही। यह पॉलिटिकल पार्टी बनाकर गांजा-भांग लेकर के यहां आया और इसमे सबसे अगुवा है रामचन्द्र परमहंस। हमने उसको देखा कि यह तो यू.पी. का आदमी हो नही सकता। यह जो रामचन्द्र परमहंस है- नया गांव हमारा असेम्बली क्षेत्र है - रागबरयारचिव गांव, उसका है। हमने रात को यहां के एस.पी. से पूछा कि बताइये यह साधु बाबा कहां का है? एक बार यह बोला कि हम आत्मदाह कर लेगे, पुनर्जन्म भगवान हमको दे देना ताकि अगले जन्म मे फिर पैदा होकर हमारे बाल-बच्चे को राम के नाम पर जलवाये। महोदया, यह आदमी रामचन्द्र परमहंस दास जो है इसके पिता जी का नाम लम्पट तिवारी है। ...**(व्यवधान)**... नया गांव का, बरियार का जहां का मैं एम.एल.ए. था, मेम्बर आफ पार्लियामेंट था। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आपको सही जानकारी नहीं है।

श्री लालू यादव : अगर आपको जानकारी दे दी तो। आप क्या बात करते हैं। आपको जानकारी कुछ नहीं होती है। आपने हर बात पर टोका-टोकी करने की आदत बना ली है। ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : आप भी सही जानकारी रखिए।

श्री लालू प्रसाद : हम तो पूरी जिम्मेदारी के साथ बोल रहे हैं। ...**(व्यवधान)**... महोदया, हमने इनके बारे में पता किया है। 13 साल की उम्र में इनकी भाभी, इनके चाचा ने इनको बकरी चराने के लिए ले जाने के लिए कहा। पता नहीं क्या हुआ बकरी के साथ? यह आरोप लगाया गांव भर के लोगों ने। हमने रात को गांव के लोगों से पता लगवाया कि भाई इसके बारे में पता करो, हमको बोलना है, इनका परिचय देना है, पता करें कि यह आदमी कौन है? तो ये हैं हमारे यहां के रहने वाले। मैं होम मिनिस्टर, आडवाणी जी से कहना चाहता हूं कि ये चार लोग अयोध्या में हिस्टरीशीटर हैं, इनके बारे में जानकारी मंगवाइये। सिंहल साहब बैठे हुए हैं, ये यहां पर डी.जी. रहे हैं, इनको तो पता होगा। इस तरह के हिस्टरीशीटर राम का नाम, जिस राम को अयोध्या के लोगों ने अपमानित करके निकाला था। अगर ये नल, नील, कोल, भील, जीव, जटायु, हथकट्टा, कनकट्टा और हनुमान नहीं होते और जो सामंतवादी व्यवस्था की पोषक सरकार, अयोध्या से निकाला था, राम से इनको कोई लेना-देना नहीं है। कृष्ण से लेना-देना इनको नहीं है, इनको गद्दी का चस्का लग गया है। महोदया, इसीलिए हमने अपने शिविर में तय किया है कि हम इनका मुकाबला करेंगे। मैं जानता हूं कि बिहार को ये लक्ष्य बनाए हुए हैं। ये दंगा कराना चाहते हैं, ये दंगा कराकर बंगाल में पहुंचना चाहते हैं, हम लोग इनकी मंशा को चूर करेंगे।

महोदया, साम्प्रदायिकता इस देश के लिए बहुत घातक है। आपने वायदा किया था, भय, भूख और भ्रष्टाचार मिटाने की बात कही थी। एक तरफ नौजवानों को कहा था कि हम हर साल एक करोड़ लोगों को काम देंगे। आज लोगों से रोजगार के अवसर छीने जा रहे हैं। इस देश के कल-कारखानों को औने-पौने दामों पर बेचा जा रहा है। मंडल कमीशन को काफी जंग और जेहाद करके हम लोगों ने लागू किया था। प्राईवेट सैक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। लोगों की नौकरी छीनी जा रही है। देश का किसान कराह रहा है, देश का श्रमिक कराह रहा है। अब जब ये जाने वाले हैं तो बता रहे हैं कि 2020 तक हमारा देश विकसित राष्ट्र होगा। देश की सरहदों पर इन्होंने जो कहा था, ढोंग किया था कि इस बार आर-पार की लड़ाई लड़ेंगे, ऐसी कमजोर सरकार हमने नहीं देखी। क्या हुआ तुम्हारे आर-पार का, क्या हुआ भय, भूख और भ्रष्टाचार का? एक तरफ तो लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि तुम बोलो, दंगा कराओ, फसाद कराओ और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम पंथ निरपेक्ष हैं। बाबरी मस्जिद गिराने वाले लोग, सात बिल्ली खाके बिलाई भई भक्तिन? हम लोग कहते हैं कि सात चूहे खाने के बाद बिलाई कहती है कि हम तो भक्तिन हैं, वेजिटेरियन हैं, हम नॉन-वेजिटेरियन पहले थे। महोदया, यह इनका भारत है। यह गांधीवाद आपके हत्यारों का है जिनकी नस-नस में साम्प्रदायिकता है। फासिस्ट ताकतें देश को ललकार रही हैं, इसलिए कांग्रेस सहित तमाम प्रतिपक्षी दलों के लोगों ने यह तय किया है कि इनको उखाड़ फेंकना है। अगर हमारा और देश का एकमात्र कोई लक्ष्य है

तो ये साम्प्रदायिक ताकते हैं जो हर जगह कम्युनलाइज़ कर रही हैं। मुझे खेद है, मुझे तकलीफ होती है कि हर जगह जो गवर्नर बहाल हो रहे हैं, राष्ट्रपति जी को सही सूची नही दी जाती है। आर.एस.एस. के लोगों को गवर्नर बनाया जा रहा है। चारों तरफ सारी संस्था को नेस्तनाबूद किया जा रहा है। चारो तरफ यह कहा जा रहा है - कहां हैं गरीबो के पास साधन? कहां है पैसा? बिहार को बांटने के बाद इन्होंने कहा था - पैकेज देंगे। इन्होने वादा किया था हरियाणा बनाएंगे। लोग कहते हैं कि लालू-राबड़ी ने रोड्ज़ नही बनाई। एन.एच. रोड खराब पड़ी है। एक ऐस्टीमेट बनकर आया लेकिन ये एक इंच भी बढ़ना नहीं चाहते हैं।

महोदया, बहुत अफसोस है कि बिहार में हर साल अंतर्राष्ट्रीय नदियो से, नेपाल से पानी आता है। वह वाटर लॉगिंग करता है और फिर पानी बहकर चला जाता है। प्रधान मंत्री जी से बिहार की मुख्य मंत्री मिली थीं, एक सर्वदलीय दल मिला था। उसने कहा था कि नेपाल से बात करिए, हाई डैम बनाइए लेकिन एक जगह भी इसका ज़िक्र नहीं है। हम चार्ज करते हैं, हमे तकलीफ है कि वाजपेयी सरकार मे पड़ोसी देशों से संबंध बिगड़े हैं - नेपाल से बिगड़े हैं, बंगलादेश से बिगड़े हैं, पाकिस्तान से बिगड़े हैं, भूटान से बिगड़े हैं। इनका इशारा है, ये रोज़-रोज़ ईश्यू बना रहे हैं। लोग कहते हैं कि भारत का नाम बदलकर हिंदुस्तान रख लो। ये तोगड़िया और इनके चट्टे-बट्टे, ये सब मिले हुए हैं। महोदया, आदि शंकराचार्य ने उत्तर और दक्षिण के पुजारियो को जोड़ने का काम किया था। ये नए ठेकेदार बने हैं। देश बचने वाला नही है। अगर ये रह गए तो देश टुकड़े-टुकड़े होने वाला है, इसलिए इनकी जो सरकार है, यह गांव, खेत-खलिहान विरोधी सरकार है, दंगा-फसाद कराने वाली सरकार है, नफरत फैलाने वाली सरकार है, माइनॉरिटीज़ के ऊपर संदेह करने वाली सरकार है। इस देश मे हिंदू-मुस्लिम-सिख-ईसाई, भारत के चार बेटे एक हुए थे लेकिन यह इस देश को विकलांग और गुमराह करने वाली सरकार है। इसलिए हम कहते हैं कि जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़कर इस देश में शुरुआत की, मंदिर हमारा टूटा नही। टूटा, चाहे न भी टूटा हो लेकिन इसके सीधे जिम्मेदार अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी हैं, मुरली मनोहर जोशी हैं। साम्प्रदायिकता नहीं होती तो इस देश पर कौन काबू पाता? आज संसद घेरे मे हैं, हम जन-प्रतिनिधि घेरे मे आ-जा रहे हैं। इसलिए यह सरकार एकदम विफल साबित हुई है। यह सरकार निकम्मी साबित हुई है। यह सरकार लुटेरी साबित हुई है। यह सरकार दंगाई साबित हुई है। इसका मुझे अफसोस है कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में इसका ज़िक्र नहीं किया है। इसलिए इस सरकार को हटाना पड़ेगा। धक्का देकर हटाना पड़ेगा। अगर नही मानेंगे तो पटका-पटकी करके गांधी बाबा के रास्ते पर चलकर इस सरकार को हटाने का निर्णय हमारे दल ने किया है। महोदया, यह असत्य का पुलिंदा है महामहिम राष्ट्रपति से जो पढ़ाया गया है। यह देश को गुमराह करने वाला है। इससे देश को बेचा जा रहा है। स्वदेशी रास्ते पर चलने का वादा किया था इन्होने देश के मतदाताओ के सामने लेकिन जो अमेरिका बोल रहा है, ये कर रहे हैं। हम लोगों ने तय किया था सर्वसम्मति से कि अमेरिका के ईराक पर हमले के विरोध मे सभी दल एक प्रस्ताव पारित करें। आज भारत को खड़ा होना चाहिए था, दोनो सदनो को खड़ा होना चाहिए था। बात कैसे पलट दी गई? दुनिया भर में अमेरिका के खिलाफ, युद्ध के खिलाफ और ईराक के पक्ष में प्रदर्शन हो रहे हैं। लेकिन हमारी सरकार, यह संसद और हम मौन क्यों बैठे हुए हैं? जब भारत के लिए निरगुट राष्ट्र, तटस्थ राष्ट्रो का नेता बनने का मौका था, उस समय वाजपेयी सरकार ने तटस्थ राष्ट्रो से बहुत पीछे फैंका है। हमारी यह संस्कृति रही है हमारी बेटियां सिंदूर लगाती हैं, आडवाणी आपने पता किया कि सिन्दूर कौन तैयार करता है? जो कपड़ा हम पहनते हैं, आप जो गेरुवा वस्त्र

पहनकर घूमते हो, इसको जुलाहे बनाते हैं जो मुस्लिम हैं। क्या आपने पता किया? किस राष्ट्रसंघ की दीवार की बात करते हो? जो चूड़ियां हमारी बेटी के हाथो मे पहनी जाती हैं, वे कौन तैयार करता है? कौन चूड़िहारा है? वह मुसलमान है। बताशा और मुकुदाना जो कि मंदिरो और मस्जिदो मे पूजा के लिए चढ़ता है, यह कौन तैयार करता है? वह मुसलमान है। कट्टरपन्थी हिन्दुत्व का नारा देकर, न कोई सरकार टिकी है और न टिकने वाली है। हम मजारो पर माथा टेकने जाते हैं। ये कौन जाता है माथा टेकने? मस्लिम से ज्यादा वहां हिन्दू जाते हैं। जो मांसाहारी लोग मुसलमान भाइयो के यहां खाने जाते हैं, क्या सिर्फ मुस्लिम जाते हैं? नही, हिन्दू जाते हैं। ये हिन्दुत्व का नारा देते हैं, क्या -क्या बात है। उस विवाद मे गोमांस किसने खाया? नही खाया? हम इस विवाद मे हम नही जाना चाहते हैं। जब तक जानकारी नही होगी, हम नही बोलेगे। महोदय, एक संघ परिवार को साल 1994 से 2000 के बीच, अखबार के अनुसार, दो सौ करोड़ रुपया संघ परिवार को मिला। देने वाली अमेरिकन कम्पनी है, जिसको फायदा हुआ है। एशियन अखबार ने लिखा है। दुनिया से पैसा आ रहा है। देश मे आग लगाओ, त्रिशूल बांटो। मुसलमान, माइनोरिटी को भगाओ। नारा दो। इस तरह से काम हो रहे हैं। हम सेवई खाने जाते हैं। ये सेवई कौन तैयार करता है? मुसलमान भाई। स्वामी विवेकानन्द जी ने शिकागो मे जाकर, पूरी दुनिया मे भारत का मस्तक ऊंचा किया था। उन्होने उस धर्म सम्मेलन को एड्रेस किया था। उन्होने भाई और बहिनो से सम्बोधित किया था। वहां पर दुनियाभर के लोग आए थे। हमारा यह सिद्धान्त रहा है, दुनियाभर मे जितने लोग हैं, सब हमारे भाई और बहन हैं। हमारे सभी धर्म गुरु लोग नतमस्तक हुए थे, स्वामी विवेकानन्द जी के नाम पर, हमारी यही संस्कृति रही है। आडवाणी जी, तोगड़िया और सिहल, ये हमको हिन्दुत्व का पाठ पढ़ाएंगे। कोई भी आपके जाल मे फंसने वाला नही है। भूल जाना ब्यूरोक्रेसी मे आप कम्युनलाइज कर रहे हो।

उपसभापति : लालू जी, टाइम हो गया।

श्री लालू प्रसाद : मैं जानता हूं ...**(व्यवधान)**... कुछ लोगो को, फायदा उठाकर गवर्नर बनाया है। यह देश टूट के कगार पर खड़ा हुआ है। यह निकम्मी सरकार है। इसलिए इसको धक्का देना पड़ेगा। अगर धक्के से नही मानेंगे तो फिर इनको अहिसंक तरीके से पटका-पटकी करके। हड्डी-गुड्डी बनाना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा। जब हम खड़े होते हैं तो ये लोग विषयान्तर करके हमारी बातों में बाधा डालते हैं। लेकिन इनकी हिम्मत नही है। देश मे लूट-खसोट मचाने वाले लोग, रोज-रोज ये कांग्रेस को डरवाते हैं। रोज-रोज सोनिया गांधी को डरवाते हैं। अरे, आप सब तो जाने वाले हो। अब यह सरकार नही रहने वाली है। ...**(व्यवधान)**... अहलूवालिया जी तो बचने वाले हैं, चूंकि मंत्री नही हैं। ये बचने वाले हैं और बाकी जाने वाले हैं। ये उस समय अफसोस करेंगे कि लालू भाई आप ठीक कहते थे, हम बेकार का जो झाल बजाते थे ठेलो का।

SHRI K. NATWAR SINGH (Rajasthan): Madam, I will not take much time of the House. I just want to mention that the hon. President of India, from paragraph 60 to paragraph 76, talked about the foreign affairs. What is striking is that not once, in his speech, did he refer to the Non-Aligned Movement! And the Prime Minister of India, at the moment, is attending the thirteenth Non-Aligned Summit! The President's Address did not make a

single mention of the fact that India is a Non-Aligned country. ...*(Interruptions)*...

THE DEPUTY CHAIRMAN: Order, please.

SHRI K. NATWAR SINGH: ....and we are a founder member of the Non-Aligned Movement. And it is said by the protagonist of this Government that non-alignment is irrelevant! Some Members of that side say that non-alignment is irrelevant. I would like to ask them "How is the North Atlantic Treaty Organisation (NATO) relevant? The Warsaw Pact has disappeared. The Soviet Union has disappeared. And NATO is expanding! Who is the enemy? The Americans are creating an enemy! What justification is there for NATO being expanded? None, whatsoever! But not a word has come from this Government to criticise the expansion of NATO. On the other hand, they are on the defensive about the Non-Aligned Movement! Non-Aligned movement is not a dogma; Non-Aligned Movement is not a doctrine. Non-alignment is a state of mind; it is how you look at the problems of the world. It is your judgment. But we are not aligned to anybody. From 1947 to 1961, there was no Non-Aligned Movement. The first summit of the Non-Aligned Movement took place in Belgrade in 1961. From 1947 to 1956 there was no Non-Aligned Movement. Nasser, Nehru and Tito met in Brioni, in 1956, and the seeds were sown for the birth of Non-Aligned Movement, which was born in 1961. But for 14 years, India did not align itself with either the capitalist camp or the communist camp. Pandit Jawaharlal Nehru, addressing the Haripura Congress in 1938, said, "Independent India will follow a foreign policy which will not be aligned either to the capitalist world or to the communist world." This has been the essence of Non-alignment. And what have they been doing the last year? The previous External Affairs Minister of India did not even utter the word "Non-alignment" when he was in office. Only when some of us, in the meeting with the Prime Minister, where Mr. Jaswant Singh was also sitting, asked, "Is India a Non-Aligned country or not?", Mr. Atal Behari Vajpayee said, "Yes, it is." Then, I asked, "What do the Foreign Minister say?" And, then, he agreed. It is only now, with a change of incumbency in South Block, that, at least, the present incumbent, Mr. Yashwant Sinha, is taking cognisance of the fact that Non-alignment is relevant. Non-alignment was relevant in the forties, fifties, sixties, seventies, eighties and nineties. The international agenda was of one kind. Today, the international agenda is changed. So, it is necessary for the Non-Aligned Group to get together, reinvent the Movement; reinvent and restructure it and make it relevant for

the 21st Century. How is it going to happen? What are the issues before the world? AIDs, drugs, terrorism, population, health, financial inequity. These are the issues on which the Non-Aligned Nations, with one voice, should speak. And who is to give the lead? It is India's duty, India's responsibility, it is India's historic role that we should take lead in getting the like-minded countries all over the world together. And, certainly, the 116 countries who are today meeting in Kuala Lumpur, should get together and raise their voice as one, as we did against colonialism, apartheid and imperialism. These are the issues which are no longer relevant in the world today because apartheid is eclipsed in South Africa, colonialism has gone because the world is run out of colonies, imperialism is finished. But a new kind of hegemony is appearing on the world scene, and it is the duty of countries like India, instead of becoming camp followers, to get up, raise their voice and say, "No. There is another point of view. We do not accept hegemony from any country, howsoever powerful, howsoever mighty." This is not to suggest that we do not want to have good relations with America. Of course, we do. It is the most powerful country; it is the richest country; it is technologically advanced. Two million Indians are living in America and doing extremely well; they have made a great name for themselves, and also for the country. At the same time, this world cannot be run by a single power which is being high-handed. Take for instance Iraq. There is one brief mention here in a feeble paragraph referring to Iraq. Not a word about condemning the proclaimed policy of the single super-power that there should be a regime change in Iraq. It is for the people of Iraq to decide whom they want as their leader. We have good relations with Iraq. I am not, for a moment, condoling everything that President Saddam Hussein has done. There is the Security Council of the United Nations. Any action against Iraq should have the sanction of the United Nations Security Council. What is the difficulty? Why is there a talk that if the Security Council does not pass the second Resolution, war is inevitable? I would like to ask there is nobody from the Government side in this House at this time to respond to what the Government of Mr. Vajpayee is doing with regard to the intentions of the single super-power against Iraq, except making pious statements, which can be interpreted either way. Even in the statement that he made in Kuala Lumpur, the language used is soft. He should have got up and said that we want the closest relations with America. But, on the matters like Iraq, crisis in West Asia, the treatment of Palestinians by the Israelis, India cannot and will not compromise. But this is not forthcoming. And, this, in any case, is against the consensus that

has been a feature of India's Foreign Policy since 1947. There has been a broad national consensus on Foreign Policy; there has been a broad national consensus on security matter. But, it is, for the first time, that there has been a crack in that consensus, there has been a division in that consensus, with regard to security matters. Now, the President says that there has been deployment of troops on the Pakistan border. For over six months, half-a-million Indian troops have been there. What was the objective? Was the objective achieved? The Deputy Prime Minister himself said that perhaps the objective was not achieved. Then why have they been sent there? Who is responsible for India's security? Neither the Congress Party, nor the RJD, nor the Smajwadi party. It is the responsibility of the Government. Why is that during their rule in Gujarat, the temple was attacked? Why is it when the Central Government is in charge of security, a temple was attacked in Jammu? It is not the responsibility of the Opposition to provide the security; it is the responsibility and duty of the Government. And, this Government has failed to provide security to the people of this country, in various parts of the country. They have been soft on terrorism. There is no example in the world of a Foreign Minister of a country taking three confirmed terrorists in his aeroplane, personal plane, flying into Kandahar and see them going to Pakistan. And, these are the three people who are responsible for the loss of many lives in Jammu and Kashmir and other parts of India. Therefore, Sir, I want to say categorically that this Government has failed to take the security of India. It has failed on the front of terrorism and it has failed in its Foreign Policy. Thank you.

THE DEPUTY CHAIRMAN: Now there are only two minutes left for the lunch hour. If you agree, we will adjourn for lunch and after lunch Mr. Singhal will be the next speaker. We have to complete the discussion today itself because there is not enough time.

SHRI S. VIDHUTALAI VIRUMBI (Tamil Nadu): Who will be the first speaker after lunch?

**The House then adjourned for lunch
at fifty nine minutes past twelve of the clock**

THE DEPUTY CHAIRMAN: After lunch, it will be Mr. B.P. Singhal and then it will go on and on. I will announce the time how much each party has got. The House is adjourned for lunch till 2 o'clock.

The House reassembled after lunch at two minutes past two of the clock.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI RAMA SHANKER KAUSHIK) in the Chair].

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, I am thankful to you for giving me this opportunity. Before I commence, I must say that, when Shri Lalu Yadav was making his speech, I was reminded of an incident that took place 40 years ago. There was a paternal land suit that I was contesting. Mr. Shanti Bhushan was my lawyer. When he appeared, he put his arguments in a very soft voice. When I came around and asked him, "Why did you speak so softly?" He said, "They are powerful arguments". Then he told me the secret. "When you have power in logic, your voice should be soft. But when you are short of logic, you have to shout".

Sir, I rise in support of the Motion of Thanks to the *Mahamahim* President of India for his inspiring and heart-warming Address to the Joint Session of the Parliament. It is quite understandable that bulk of the Opposition Members had felt extremely uncomfortable when the President was recounting in paragraphs after paragraphs the concrete and startling achievements made by his Government. Unfortunately, for the Opposition the contrast of achievements in four years as against the total achievements in 40 years or more, is far more glaring for the comfort of the Opposition. Whether it was the availability of telephone or gas connections, or, the construction of four or six lane highways, or, whether it was transmission of money through money orders, the achievements had been 100-150 fold. It is unprecedented and the achievements in the last four years were far more than what were achieved in 40 years. Whether it was the record-setting discovery of new oil finds, whether it was power generation at the rate of 1,000 megawatts per year, whether it was the installing of biogas plants or power units in large numbers, it is all baffling the Opposition. The Kisan Credit Cards, issued to 2.4 crore Kisans, is a record in itself. The forest cover, which used to be constantly in the negative, registered a positive increase of 1.9 per cent. The 'Mahila Samakhya Programme' which spread

into 9,000 villages in 60 districts was absolutely incredible for the Opposition. Sir, the IT sector has really baffled not only the Opposition but even the world. It has been recognised the world-over as a phenomenon unique to India. The vocational schools, the linkage of universities with the science and technology researchers has been achieved for the first time and this has brought the universities in the field of research. The 'Sampoorna Gram Rozgar Yojana' generated 11 crore 60 lakh man days of work. But, they say that this Government has been a failure on all the fronts. These are the signs of the so-called failure.

The Freedom of Information Bill, talked about for a long time, was brought by this Government. The fundamental Right to Education for every child, talked about for the last 25 years, was brought by this Government. But, this Government is supposed to have failed on all the fronts according to the Leader of the Congress Party, Shrimati Sonia Gandhi.

This is an index of how the Opposition judges the achievements. In the international field, India today commands profoundly more respect than it has ever commanded earlier to this, not merely because of the nuclear capability shown at Pokhran but also because of the bewildering heroism exhibited by our Jawans in the Kargil war even while the Government was abiding by its moral stand of not violating the LoC in the war. These have brought about unprecedented respect to our country.

Sir, it is true that the problems are vast. But, they have to be so. Having inherited numerous blunders of history, not only this Government but all the future Governments will have to carry the load of liabilities on their back such as the short-sighted policy in dealing with Kashmir and making it a mess, the roughshod policy in treating the North-East in the earlier stages, the acceptance in totality of the Pay Commission's recommendations without complying with a very important recommendation in that Report of cutting down the bureaucratic flab by 30 per cent and was not heeded to. Virus of greed and corruption, criminalisation of politics coupled with politicisation of criminals and accentuation of casteism and communalism are the backbreaking legacies of yester years that the country is carrying today.

Sir, of the four limbs of democracy, the process of breaking the back of the bureaucracy started in the early 60s. By the mid 70s, process was complete and the bureaucracy's spine had been decimated. The

Legislature elbowed out the Bureaucracy. Then, came a time during the Emergency, when there was a cry of committed Bureaucracy. It even went to having a committed Judiciary. Thank God, the people rejected it. But, then came the time when the Judiciary has now elbowed out the Legislature as well as Bureaucracy; for it is taking decisions, which properly relate to the domain of the Executive and the Legislature. Till yesterday, Sir, the Legislature had elbowed out the Executive. Today, we are seeing how the Judiciary is elbowing out both the Legislature as well as the Executive by merrily giving decisions, which belonged to their domain. A more dangerous trend has already started and we are now approaching a tomorrow where the fourth pillar of democracy, *i.e.*, the media is very systematically elbowing out even the Judiciary by conducting their own media trials or brazenly giving various options available to the Supreme Court in cases which happen to be *sub-judiced* with the Apex Court. The audacity of it all does not augur well for the country. Today the tragedy of India is that all the four limbs of democracy have thrown discipline to the winds and it is free for all. The most frightening aspect of this scenario is that justice, honest ideology and convictions have been thrown in the boot of the car while money power and money power alone is in the driving seat of all these four limbs. In such a scenario, not merely the Treasury Benches but also the Opposition will have to reckon the heavy odds that have to be battled with successfully to put the country back on the road where truth, integrity and justice are treated with the respect that is due to them.

The ills are there. The shortcomings cannot be denied. But, it is a pity that the Opposition has harped only on the dark aspects of the national polity and turned a blind eye to the remarkable achievements made against such heavy odds.

The Members sitting in this House and in the Lok Sabha comprise the totality of the top leadership of this country. I consider it my duty to point out two very dangerous developments which if not rectified in time can prove disastrous for the country. The first is the double standards that have come to shape the response of the leaders of the pseudo-secularist's camp on the question of prestige and respect with which the judiciary should be treated.

श्री प्रेमचन्द गुप्ता (बिहार) : अध्यक्ष जी, पढ़कर कोई बोल सकता है क्या?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : उनको अपनी बात कहने दीजिए।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : नॉर्मली पढ़कर नही बोलते हैं। इस साईड से कोई पढ़कर बोलता है तो आप उसको एलाऊ नहीं करते हैं।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सब एलाऊ कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक): वैसे आपकी बात सही है ...*(Interruptions)*...

SHRI PREM CHAND GUPTA: Let us not destroy the tradition of the House. I have nothing against him ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया बैठिए ...**(व्यवधान)**... कृपया आप आसन ग्रहण करें। यह बात सही है। **जहां तक** परंपरा का सवाल है ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : नाईमन साहब ने अपना भाषण पढ़ा था, चो रामास्वामी ने भी अपना भाषण पढ़ा था।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपके संरक्षण के लिए मैं मौजूद हूं ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : जी, धन्यवाद।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : अगर उन्होंने पढ़ा है तो गलत किया है। If Shri Cho S. Ramaswamy had read his speech, he did not do justice to the House. Sir, he should not follow something wrong.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, इनको तो अपना भाषण पढ़ने की इजाजत मिलनी चाहिए क्योकि ये तो पुलिस अफसर रहे हैं। ये राजनेता तो हैं नहीं। ये तो लिखकर ही लाएंगे ना। इसलिए इनको पढ़ने दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : वैसे यह बात सही है और हमारा भी जो अभ्यास रहा है तथा हमने जहां-जहां यह व्यवस्था देखी है, जैसे उत्तर प्रदेश की विधान सभा मे व्यवस्था यह है कि पढ़कर भाषण नहीं दिया जाता लेकिन जहां तक मैंने देखा है, राज्य सभा मे यह व्यवस्था चल रही है, यह परंपरा चल रही है।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : आप कहां एलाऊ करते हैं? इस साईड में अगर कोई पढ़कर बोलता है तो आप उसे बोलने नहीं देते हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : नहीं, ऐसा नहीं है। सिंहल साहब, आप अपनी बात जारी रखिए।

SHRI B.P. SINGHAL: The double standards have become the symbol of the pseudo-secularists. They do not seem to comprehend that while they may not be intending so, but they depict a picture of being anti-Hindu, from the way they are behaving and from their reactions. That is what I am trying to say. When the Supreme Court gives any judgement on the issue of Ram Janambhoomi and the VHP says something else, all heavens are fallen. At the same time, they maintained a deafening silence when the Chief Minister of Karnataka refused to abide by the Supreme Court orders in regard to giving water. My colleagues of the Left, ...(Interruptions)...

श्री लालू प्रसाद : महोदय, कैसे एलाऊ करेंगे ...**(व्यवधान)**... ये ख्वाह-मख्वाह जुडिशियरी के खिलाफ बोल रहे हैं ...**(व्यवधान)**... जो इनके कार्ड के खिलाफ बात हो रही है, इसे प्रोसीडिंग्ज से निकाला जाए ...**(व्यवधान)**... How can he speak against the judiciary? ...*(Interruptions)*... They are playing a Hindu card. ...*(Interruptions)*...

SHRI B.P. SINGHAL: I am talking of the reaction and response of pseudo-secularists...*(Interruptions)*... My colleagues on the Left, unabashedly and openly hailed Arundhati Roy, who not only defied but even insulted the Supreme Court; that is the respect they give to the Supreme Court. There was a death-like silence when the Supreme Court ordered a ban on the strike by the Bar Council.

SHRI M.V.RAJASEKHARAN (Karnataka): Sir, there is a reference to the Chief Minister of Karnataka, at the time of the President's Address.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कार्रवाई देख ली जाएगी, अगर उसमे कोई अनुचित बात है तो वह हटा दी जाएगी।

SHRI B.P.SINGHAL: There was a death-like silence, when the Supreme Court banned the strike by advocates. But, they merrily defied it. Nobody commented. I can tell you, Sir, the voices have never been raised. ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : आप बोल रहे हैं कि किसी ने किया। पूरे देश को कर रहे हैं ...**(व्यवधान)**...

SHRI B.P.SINGHAL: मैं अपोजिशन की बात कर रहा हूं। He is an independent one.

श्री लालू प्रसाद : महोदय, मैं व्यवस्था पर खड़ा हूं। सुप्रीम कोर्ट अयोध्या का सेंसिटिव मामला सुन रहा है। इन्होंने पिटीशन डाला है। अभी जो मोदी, तोगड़िया, विश्व हिन्दू परिषद ने भड़काऊ भाषण दिया उसके बारे में जो नोटिस इनको दिया है जिसको यह कंडम कर रहे हैं। यह है इनका भाव। इनके पक्ष में सुप्रीम कोर्ट कहे तो ठीक है लेकिन नहीं कहे तो ...**(व्यवधान)**...

SHRI B.P.SINGHAL: आपकी समझ में नहीं आ रहा है यह। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : वह उसमें नहीं बोल रहे हैं।

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : वह और क्या बोल रहे हैं। सारा हाऊस सुन रहा है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठें, आसन ग्रहण करें।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : दोसीपुरा, वाराणसी में दो कब्रों के स्थानांतरण के लिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट अक्तूबर, 1986 में हुआ, आज तक कम्पलाइंस नहीं हुआ। किसी ने नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट की ऐसी अवहेलना क्यों हो रही है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप क्या कहना चाहते हैं?

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : मैं यह कह रहा हूं Double standards of judging actions. अपने जब माफिक हो तो चुप, दूसरा कोई कहे तो चिल्लाते हैं। ...**(व्यवधान)**...मैं तो बतला रहा हूं। एस.वाई.एल. केनाल का आर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया, उसका कम्पलाइंस नहीं हो रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। ...**(व्यवधान)**... इतना ही नहीं है सर, This is not all and even more dangerous development is infecting the polity. When the Supreme Court...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया इतना ध्यान रखें कि आपके दल के केवल अब कुछ ही मिनट बचे हैं। ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्द्र प्रकाश सिंहल : मान्यवर, मैं अपने समय में ही समाप्त कर लूंगा। The Supreme Court tended to a clear finding that there was no *saffronisation* of the books. That whatever was done by NCERT was proper. But, how did the Opposition-led Governments react? They said that they do not accept it. They will not accept those books. Shri Eduardo Faleiro gave an example, I suspect, terming a book as phoney, because there cannot be two editions of the same book. I am urging to send a letter, sending a copy of the book so that it can be examined that those kinds of things cannot be contained in the books. Anything is happening today. But, they

refused to respect the Supreme Court. Sitting Judge of the Supreme Court was in a Commission to examine the Stains murder case. It came to a clear finding that there was no hand of the Bajrang Dal. But, I have heard the Catholic spokesman saying in my presence that they do not accept that verdict. Meaning thereby, any verdict, which is in tune with their stand, is fine; any verdict which is against them is to be suspected. Now, the second dangerous symptom, Sir, is that Goebbleseon tactics is going on. एक असत्य बोलो, और खूब प्रोपगंडा करो, यह सत्य माना जाएगा। ...**(व्यवधान)**... झबुआ नन केस को वी.एच.पी. द्वारा किया हुआ बताया गया, स्टेन्स मरडर को बजरंग दल द्वारा किया हुआ बताया गया। इसके संबंध में 21 आर्टीकल्स निकले, छह एडोटोरियल निकले और वी.एच.पी. को एक से एक गाली दी गई। जब पता लगा कि इन दोनों मे इनका हाथ नहीं है तो किसी ने माफी नही मांगी। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : सबमें हाथ था।...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : आन्ध्र प्रदेश मे बम ब्लास्ट हो रहे थे, कर्णाटक में, गोवा मे, एक मस्जिद मे भी ब्लास्ट हुआ और बड़े बेहूदा किस्म के प्रोवोकेटिव पोस्टर्स पूरे भारत मे वी.एच.पी. के नाम से चिपकाए जा रहे थे। बहुत जबरदस्त गाली दी जा रही थी, यह तो भगवान की कृपा थी कि अंजुमन दीदार वाले जब पकड़े गए और उनके यहां पर वे सारे बम मिले और उनके यहां पोस्टर्स के बक्से भरे हुए मिले, तो सब भेद खुला। उसके बाद से बम ब्लास्ट होना बंद, पोस्टर चिपकाना बंद। किसी ने नही कहा कि हम यह गलत आरोप लगा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : हम माफी चाहते हैं। मेरा कहना यह है कि इस पोलिटिक्स मे कुछ मॉरेलिटी लाने की आवश्यकता है, कुछ नैतिकता आये। जब तक यह नहीं आयेगी, यहां पर बैठे हुए एक सदस्य खुलेआम कहते हैं कि मैं यहां की मर्यादाओं को भंग करने के लिए आया हूं और यह सारा सदन चुप रहता है, हद है।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप कृपया समाप्त कीजिए।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : उन सभी सदस्यों को जो नीचे सिर करके बैठे हुए हैं। धन्यवाद। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : यह शब्द निकाल दिया जायेगा। ...**(व्यवधान)**... हां, यह गलत शब्द है, यह कार्यवाही में नहीं आयेगा। ...**(व्यवधान)**... यह शब्द कार्यवाही से निकाल दिया गया है।

---

* Expunged as ordered by the Chair.

श्री लालू प्रसाद : इस शब्द को निकलवाइये। इनसे माफी मंगवाइये।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कार्यवाही से निकाल दिया है।

श्री लालू प्रसाद : नही, *शब्द को वापस करवाइये। इनसे माफी मंगवाइये।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : कार्यवाही से निकाल दिया है। ...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**... चेयरमैन साहब, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : अपने सदस्यो को *दें। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप कृपया आसन ग्रहण कीजिए। ...**(व्यवधान)**... हां, हां।

श्री लालू प्रसाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, इनसे ये शब्द वापस करवाइये। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपने जो *शब्द इस्तेमाल किया है। ...**(व्यवधान)**... माननीय सदस्यो के लिए जो *शब्द आपने यूज किया है, आप उसको वापस ले लीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : सर, मैं कहूंगा शर्म की बात है। ...**(व्यवधान)**... *की जगह पर लज्जाजनक है। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : उपसभाध्यक्ष महोदय, ये विश्व हिन्दू परिषद की बात करते हैं। जब इंग्लैंड मे वहां की सरकार ने गाय को मारा तो ये क्या कर रहे थे?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ठीक है। आप बैठिए।

श्री लालू प्रसाद : इंग्लैंड मे हजारो जर्सी गायों को मार दिया गया। कहां थे आपके विश्व हिन्दू परिषद वाले? ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप बैठ जाइये। लालू प्रसाद जी आप बैठ जाइये। ...**(व्यवधान)**... माननीय राजीव शुक्ला। उपस्थित नहीं हैं। माननीय शंकर राय चौधरी?

---

*Expunged as ordered by the Chair.

मौलाना ओबैदुल्लाह खान आज़मी (मध्य प्रदेश) : सबको* कहा जा रहा है। वैसे ये भी तो इस हाउस के सदस्य हैं, उनको भी कह रहे हैं कि* ...**(व्यवधान)**... ये सबको * कह रहे हैं। ये सभी सदस्यों पर * फेर रहे हैं। सदस्य तो ये भी हैं। ये सभी को गाली दे रहे हैं। ये सभी एमपीज को गाली दे रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : उन्होने वापस ले लिया है। माननीय शंकर राय चौधरी। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद : ये माफी मांगे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : इन्होंने वापस ले लिया है। शांति, शांति। ...**(व्यवधान)**... माननीय शंकर राय चौधरी। ...**(व्यवधान)**... माननीय शंकर राय चौधरी। ...**(व्यवधान)**... माननीय शंकर राय चौधरी।

श्री शंकर राय चौधरी (पश्चिमी बंगाल) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर आज चर्चा हो रही है। इस संबंध में सरकार ने अपने जो प्रोग्राम्स हैं, उनके बारे मे जिक्र किया है और कई चिंताओ को, कई मुद्दो को प्रकाशित किया है। मैं सिर्फ दो पैराग्राफ को जोड़कर अपनी बात कहना चाहूंगा। सबसे पहले पैराग्राफ सात में सरकार ने कहा है- National security is a matter of highest priority for my Government. यानी सरकार की सबसे ऊंची priority नेशनल सिक्योरिटी है और पैराग्राफ पंद्रह में कहा है - My Government has repeatedly made it clear that the Ayodhya dispute can be resolved.

इसी संदर्भ में मैं नेशनल सिक्योरिटी के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सरकार ने जो अपनी चिंता इसमें व्यक्त की है, उसके संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान इतिहास के 1980 के दशक के पंजाब की तरफ ले जाना चाहूंगा। हम भूल गए हैं कि 80 के दशक में राजनीतिक दांवपेचों के कारण उस समय की केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने वहां कुछ ऐसी शख्सियतों को खड़ा किया था जिनसे धर्म के नाम पर काफी अस्थिरता पैदा हो गई थी। जिन शख्सियतों को उन्होंने खड़ा किया था, अंत में वे शख्सियतें उन राजनीतिक दलों के काबू से बाहर हो गईं और देश को एक बहुत बड़ा झटका लगा। एक बहुत बहादुर और वफादार कौम पर कई जगहों पर कातिलाना हमले हुए और उस झटके को संभालते-संभालते हमारे मुल्क को काफी कठिनाई झेलनी पड़ी। उसके ज़ख्म शायद अभी तक पूरी तरह से भरे नहीं हैं। इसी संदर्भ में मैं सरकार का ध्यान आज के हालात की ओर ले जाना चाहूंगा क्योंकि मैं समझता हूं कि इतिहास में एक बार झटका हमें लग चुका है और आज अयोध्या और हिंदुत्व के मुद्दे पर देश में जो हालात खड़े किए जा रहे हैं, अगर ये हालात और बढ़ने दिए जाएंगे तो 80 के दशक में पंजाब में हमें जो झटका लगा था, शायद हिंदुस्तान में फिर वैसा ही झटका कहीं और लगने का अंदेशा है। इसी संदर्भ में मैंने कहा था कि पंजाब में जिन शख्सियतों को खड़ा किया गया था और जिस राजनीतिक दल ने उसको खड़ा किया था, उससे वे शख्सियतें बेकाबू हो गईं और इतना बड़ा सदमा, इतना बड़ा झटका देश को लगा। आज मैं मानता हूं कि हिंदुत्व के नाम पर वैसी ही शख्सियतें उभर रही हैं। उसमें मैं डा. प्रवीण तोगड़िया का नाम ले रहा हूं जो मेरे ख्याल से ...**(व्यवधान)**...

श्री ललितभाई मेहता (गुजरात) : उपसभाध्यक्ष जी, किसी का नाम यहां लिया जा सकता है क्या?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठिए, ऐसी कोई बात नही है। नाम लिया जा सकता है। इसमे कोई ऐसी बात नही है।

श्री ललितभाई मेहता : महोदय, सदन मे जो उपस्थित नही हैं, ऐसे व्यक्तियो का नाम क्या लिया जा सकता है?

SHRI SATISH PRADHAN (Maharashtra) : Sir, the name of a person who is not present and cannot defend himself, cannot be taken in the House. His name should be deleted. These are the Rules of Procedure and Conduct of the Business in the House.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : जो एक बड़ा संगठन इस समय अपने को कह रहा है, उस संगठन के वे पदाधिकारी हैं। नाम लिया जा सकता है। आप आसन ग्रहण करे। ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : अगर नाम न लेने की मर्यादा यहां समाप्त करने वाले हैं और किसी का भी नाम लिया जा सकता है तो हम भी नाम लिया करेंगे।

एक माननीय सदस्य : करो, करो, कौन रोकता है?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अब आप बैठिए।

श्री शंकर राय चौधरी : अब ओसामा बिन लादेन का नाम भी नही लेगे क्या?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : मैंने व्यवस्था दे दी कि तोगड़िया साहब अपने को एक बहुत बड़ा कहने वाले संगठन के पदाधिकारी हैं। उनका नाम लिया जा सकता है।

श्री लालू प्रसाद : साहब कहां है? तोगड़िया तो दंगाई है, बलवाई है। तोगड़िया का नाम तो बच्चा-बच्चा लेता है।

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : लालू से बड़ा बलवाई कहां मिलेगा?

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप क्या बात कह रहे हैं यह?

श्री लालू प्रसाद : पोटा मे बंद करवा देंगे।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप जारी रखिए। ...**(व्यवधान)**...

मौलाना ओबैदुल्ला खान आज़मी : लालू दंगाई को जेल में डालने वाला, इतिहास बनाने वाला पुरुष है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : अरे आप बैठिए। ...**(व्यवधान)**... अब आप आसन ग्रहण करें और इनको बोलने दीजिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री लालू प्रसाद: जेल हमारा गुरुद्वारा है। ...**(व्यवधान)**... पोटा में एक-एक को रस्सी से बांधकर भेजेंगे। तिहाड़ जेल में इनको चने भी नहीं मिलेंगे। ...**(व्यवधान)**...

श्रीमती सरोज दुबे : अगर इनकी सरकार रहेगी तो ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप इनको बोलने दीजिए। सरोज दुबे जी शांत रहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री शंकर राय चौधरी : तो मैं डॉ. प्रवीण तोगड़िया का नाम ले रहा हूं। मैं उनको हिटलर और हिन्दुत्व का खिताब दे रहा हूं। मुझे यह डर है कि अगर इन पर काबू नहीं पाया गया तो हमने 1980 में पंजाब में जो झटका खाया था, वह झटका और लगने वाला है। इसलिए मैं सरकार से यह दरियाफ्त करूंगा कि इस शख्सियत और इनसे जुड़ी हुई जो शख्सियत हैं, उन पर काबू पाया जाए। ...**(व्यवधान)**... सुनिए। पोटा एक बहुत अच्छा कानून है। उसके बनाने के वक्त यह बताया गया था कि यह खास मौकों पर लगाया जाएगा। यह कई जगह लगाया गया है या नहीं लगाया गया है। हम यहां इस बहस में नहीं पड़ रहे हैं कि यह सही लगाया गया है या गलत लगाया गया है। लेकिन यह एक केस है जहां पोटा लगाया जाना चाहिए। मैं सिर्फ केन्द्र सरकार की तरफ अंगुली नहीं उठा रहा हूं। क्योंकि यह शख्सियत पोटा लगाने वाली सिर्फ केन्द्र सरकार नहीं है, राज्य सरकार भी है। अगर वह चाहे तो पोटा लगा सकती है। मैं दोनों से पूछता हूं कि अगर यह आदमी खतरनाक साबित हुआ है, अगर किसी वजह से केन्द्र सरकार ने इस पर पोटा नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया, मैं इस पर भी बहस नहीं करूंगा। राज्य सरकारों पर क्या रुकावट थी जब उन्होंने उनके राज्य में जाकर भाषण दिए और उन्होंने पोटा नहीं लगाया। अगर वाकई यह लगाना था सिर्फ केन्द्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी लगा सकती थी। ये कई स्टेट्स में गए। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठ जाइए। ...**(व्यवधान)**... शांत रहिए। ...**(व्यवधान)**...

श्री शंकर राय चौधरी : दूसरी बात है कि त्रिशूल आवंटन हो रहा है। त्रिशूल शंकर भगवान का प्रतीक है और शंकर भगवान की हम पूजा करते हैं। लेकिन हम कानूनी बाल की खाल उतार रहे हैं कि वह चार इंच लम्बा है, पांच इंच लम्बा है, कानूनी है, गैर कानूनी है। बाल की खाल उतारने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इसके बांटने से देश में साम्प्रदायिकता का भाव उभर रहा है। इस पर भी काबू पाना चाहिए। मैं सिर्फ केन्द्र सरकार को ही नहीं, राज्य सरकारों को भी यह बता देना चाहता हूं कि अगर वे इस पर पाबंदी लगाना चाहती हैं तो राज्य सरकारें भी क्यों नहीं लगाती? क्या देश की अखंडता, रक्षा की जिम्मेदारी सिर्फ केन्द्र सरकार की है?

राज्य सरकारो का इसमें कोई हाथ नही है? मुझे इसका जवाब चाहिए। तीसरी बात है गुजरात और गोधरा की। ठीक है वहां ऐसा हुआ है, मैं इसको भी यहां नही उठाना चाहता हूं। मैं सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी के तौर से एक बात कह रहा हूं कि जब पंजाब मे हमे झटका लगा था तब पाकिस्तान ने पूरा फायदा उठाया था, और उस हालात पर काबू पाने के लिए, हमे जानमाल का काफी नुकसान उठाना पड़ा। गुजरात मे जब ये हालात हुए तब एक ऐसा मोर्चा खोला गया, जिस पर काबू पाने के लिए डिप्लॉयड सेनाओ से हमे कुछ सेनाएं वापस बुलानी पड़ी क्योकि उस पर दुरुस्त तरीके से काबू नही पाया गया। चाहे वह गलती केंद्र सरकार की हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की हो। मैं यह कहता हूं कि वही गुजरात गवर्नमेंट, वही पुलिस, वही सरकार थी लेकिन जब केंद्र ने उन पर उंगली उठाई, दबाव डाला तो अक्षरधाम की घटना के बाद फिर किसी किस्म का रिएक्शन नही हुआ। उन्होने बहुत दुरुस्त तरीके से रिएक्ट किया। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं और जब महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर चर्चा कर रहे है तब देश की नेशनल सिक्योरिटी, इसकी इंटेगरिटी की जिम्मेदारी सिर्फ केंद्र सरकार की नही है, हम लोगो पर भी है। सब लोग मिलकर इस पर काम करे।

तीसरी बात यह है कि इसमे राष्ट्रपति जी ने पैराग्राफ नम्बर तेरह पर इस बात का जिक्र किया है कि इल्लिगल माइग्रेशन बंगलादेश से हो रहा है। इसमे कोई शक नही है कि इल्लिगल माइग्रेशन रोकने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बॉर्डर मैन्ड करती है, इसमे भी कोई शक नही है। लेकिन हमारे पूर्वांचल के जितने भी सूबे हैं, राज्य और प्रदेश हैं, वहां से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स उठाकर पश्चिम मे ले आते हैं। मैं मानता हूं कि यहां जरूरत है लेकिन उस बॉर्डर को नंगा करके छोड़ने का क्या मतलब है? उसके बाद हम कहते हैं कि इल्लिगल माइग्रेशन होता है ! हो ! होना तो है ही। बिल्कुल होना है। पश्चिम मे एक बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सिर्फ बीस से पच्चीस किलोमीटर तक का बॉर्डर संभालने के काबिल है। हमारे पूर्वांचल के राज्यो को, चाहे पश्चिम बंगाल हो, असम, त्रिपुरा या कोई भी हो, पचास से अस्सी, नब्बे तक का बॉर्डर एक बटालियन संभाल रही है। बिल्कुल खुला पड़ा है। दरवाजे बिल्कुल खुले पड़े हैं। जिसको आना है वह आए-जाए। उसके बाद हम इल्लिगल माइग्रेशन की बात करें ! लेकिन यहां भी गलती सिर्फ केंद्र सरकार की नहीं है। केंद्र सरकार की जिम्मेदारी इल्लिगल माइग्रेशन रोकना है, ठीक बात है, लेकिन एक लीगल माइग्रेशन होने के बाद उन सूबो मे, उन प्रदेशो में, उन राज्यों में जो ये लोग बस गए हैं इसकी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की नही है। इसकी जिम्मेदारी उन राज्यों की है जिन्होने उन्हे यहां बसाया है। यह आज की बात नही है। यह बात तकरीबन बीस, तीस, चालीस साल से चल रही है। अगर हम वाकई नेशनल सिक्योरिटी पर जोर देना चाहते हैं तो आइए दोनो तरफ मिलकर काम करें। यह एक आदमी की जिम्मेदारी नही है। एक पक्ष की जिम्मेदारी नही है।

त्रिपुरा मे अभी इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छी बात है, इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन यहां भी राजनीतिक दांवपेंचों में कुछ पोलिटिकल पार्टीज ने कुछ ऐसे मिलाप किया है, इलेक्शन के लिए उन्होने ऐसे जोड़ बनाया है, जिसमें एक पार्टी, वहां जो हमारे सेपेरेटिस्ट एलिमेंट है - नेशनल लिब्रेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा, उनके साथ मिले हुए हैं ...**(व्यवधान)**...

श्री भारतेन्दु प्रकाश सिंहल : नाम बोलिए, नाम क्यो नही बोलते हैं ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : उन्हे जो बोलना है, बोलेंगे ...**(व्यवधान)**...

श्री शंकर राय चौधरी : मैंने किसी पोलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लिया है (व्यवधान)..न ही मैं लूंगा ...**(व्यवधान)**...

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : यह पुलिस थाना नही है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आपके कहने से नही बोलेगे .(व्यवधान)..आप कृपया आसन ग्रहण करे ...**(व्यवधान)**...

श्री शंकर राय चौधरी : इसके नतीजे बुरे निकलेगे। यह हमने कई स्टेट्स में अनुभव किया है। मैं सरकार की सराहना करता हूं कि नॉर्थ-ईस्ट में पीस प्रोसेस पर उन्होंने काफी बढ़ावा दिया है। अच्छा बढ़ाया दिया जा रहा है। लेकिन यह मेरा खुद का मानना है और नॉर्थ-ईस्ट पीस प्रोसेस से मैं यह उम्मीद भी रखता हूं कि कश्मीर में जो गलती की है, वैसी न करे। नॉर्थ-ईस्ट में जितनी पार्टीज हैं उनके साथ मिलकर, असम, त्रिपुरा या जो-जो कंसर्न्ड हैं उन सबको लेकर चले। अभी देखा जा रहा है कि वे सिर्फ एन.एस.सी.एन.(आई.एम.) के साथ बात कर रहे हैं। वहां की जो दूसरी नागा पार्टीज हैं उनके साथ बात नही हो रही है। सबके साथ मिलकर, मेलमिलाप से बात करे।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इतना कहकर मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण पर अपने कमेन्ट्स समाप्त करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं और उम्मीद रखता हूं कि हमारी सैंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट अपनी-अपनी जगह, अपना-अपना काम करें। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : माननीय बी.जे.पाण्डा। इस समय नहीं हैं। श्री नानाजी देशमुख।

श्री नाना देशमुख (नाम-निर्देशित) : उपसभाध्यक्ष महोदय, महामहिम राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे 2020 तक भारत को विकसित देश के रूप में देखने का जो हेतु प्रकट किया है उसके लिए मैं राष्ट्रपति का बहुत आभारी हूं। किन्तु दुख के साथ मुझे एक बात कहनी पड़ रही है कि राष्ट्रपति जी के ध्यान से एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ओझल हो गई है। आपको और हमको पता है कि इस सरकार ने सदन के सभी सदस्यों की सद्भावना का लाभ उठा कर 6 साल से 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने का, मौलिक अधिकार देने का प्रस्ताव पास कराया और सब ने बड़ी खुशी के साथ इस प्रस्ताव का सर्वसम्मति से अनुमोदन किया, किन्तु इसको कार्यान्वित करने की दृष्टि से यह सरकार तब से अब तक कुछ कर रही है, ऐसा दिखाई नही देता। अभी 5 फरवरी, 2003 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" मे एक सर्वे छपा है। उस सर्वे मे कहा गया है कि देश के 40 प्रतिशत बालक और 50 प्रतिशत से अधिक बालिकाएं प्राथमिक विद्यालयों में अपना नाम तक नहीं लिखा पा रही हैं। इसका अर्थ यह है कि मौलिक अधिकार तो प्रदान किया है, किन्तु उसे कार्यान्वित करने की ओर सरकार आज तक कोई, किसी

प्रकार का कदम नही उठा रही है। राष्ट्रपति महोदय ने इस ओर सरकार को कोई निर्देश दिया है ऐसा उनके भाषण मे मुझे नही मिला। अपने देश मे जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग है उसकी रिपोर्ट कहती है कि देश मे 298 मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय चल रहे हैं और उनके अंतर्गत 10,600 डिग्री कॉलेजज़ काम रहे हैं। इन 10,600 डिग्री कॉलेजज़ में 1,99,507 प्राध्यापको की संख्या है। इन डिग्री कॉलेजज़ मे पढ रहे युवक-युवतियों की संख्या 75 लाख से अधिक है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अरबों रुपया इनके ऊपर खर्च कर रहा है। किन्तु यह विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो कि खूब पैसा दे रहा है, तनख्वाह दे रहा है, क्या वह इनको यह नहीं कह सकता या प्रेरित नही कर सकता कि छुट्टियों के काल में, लगभग दो लाख प्राध्यापक और 75 लाख युवक-युवतियां अपने-अपने क्षेत्र में जा कर, इन बच्चों को, जो कि 6 साल से 14 साल तक की आयु के हैं। इन्हे पढ़ाने की दृष्टि से प्रेरणा का काम करे। यदि ये सब जुट जाएं छुट्टियो मे, तो वर्ष 2020 मे जो भारत को हम विकसित राष्ट्र के रूप मे देखना चाहते हैं उसमे एक बहुत बड़ा योगदान इनका होगा। आज प्रतिभा पलायन हो रहा है, किन्तु यदि विश्वविद्यालयो मे पढने वाले ये युवक युवतियां तथा प्राध्यापक गांवो मे जाकर इन अभागे बच्चो को, जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के अंतर्गत हैं, को पढ़ाने का काम करेगे तो देश की परिस्थिति उन्हें देखने को मिलेगी और परिस्थिति देखकर कुछ करने की प्रेरणा उन्हे प्राप्त होगी। इससे राष्ट्रपति जी ने जो अपनी इच्छा और अपने देश की सरकार का जो विश्वास प्रकट किया है, वह साकार होगा। किन्तु, केवल कानून बनाकर पास करवा देना या केवल मौलिक अधिकारो का पालन करवा देना या किसी भी प्रकार के सरकार द्वारा कदम आगे उठा देना, इससे तो वर्ष 2020 तक इस देश को विकसित राष्ट्र के रूप में देखने का सपना केवल सपना मात्र रह जाएगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राष्ट्रपति महोदय के ध्यान मे हमारी यह भावना पहुंचे और वे अपनी सरकार को इस प्रकार के आदेश दें कि मौलिक अधिकार तो प्रदान किए जाते हैं, लेकिन उसको कार्यान्वित करने की दृष्टि से कुछ भी न करना यह उचित नही है। बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, लेकिन आज तक भारत में स्थिति क्या बनी? एक तिहाई से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे किसी ढंग से अपनी जिंदगी बिता रहे हैं और देश मे बढ रही सतत बेकारी काबू मे नही आ रही है। इसका कारण है कि जो हम निर्णय करते हैं, निश्चय करते हैं, उसके अनुसार कार्यान्वयन करने की तरफ कोई ध्यान नही देते, केवल प्रस्ताव पारित करते हैं, बड़े बड़े भाषण देते हैं, कार्यक्षेत्र मे कार्य करने की ओर किसी को रुचि दिखाई नही देती।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मेरी आपसे प्रार्थना है कि सदन की इस भावना को आप कृपा कर महामहिम राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाने की कृपा करें। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री शाहिद सिद्दिकी।

श्री शाहिद सिद्दिकी (उत्तर प्रदेश) : महोदय।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप अपनी सीट से नही बोल रहे।

श्री शाहिद सिद्दिकी : सर, आपकी इजाजत लेना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आपके दल के केवल दो मिनट शेष हैं। चूंकि आपकी मेडेन स्पीच है इसलिए आपको मैं थोड़ा ज्यादा समय दूंगा, लेकिन आप भी जरा ध्यान रखिएगा और जल्दी अपनी बात खतम कीजिएगा।

श्री शाहिद सिद्दिकी : धन्यवाद, महोदय। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में वर्ष 2020 में एक ऐसा भारत बनाने की बात कही है, जहां लोगों को इंसाफ मिलेगा। आज से 80 साल पहले इस देश के एक बूढ़े ने, जिसका नाम महात्मा गांधी था, ऐसा ही एक सपना देखा था, रामराज बनाने का सपना। आज हम उस रामराज बनाने के सपने को कहां तक पहुंचा पाए हैं? उस रामराज में क्या था? उस रामराज में महात्मा गांधी क्या चाहते थे? वह ऐसा राज चाहते थे, जहां शेर और बकरी एक घाट पर पानी पिएं, जहां हिन्दू और मुसलमान को इंसाफ मिले, जहां कानून में फर्क न हो, जहां लोगों के बीच कोई भेदभाव न हो। ऐसे रामराज की बात उन्होंने की थी। मैं अपने साथियों से और इस माननीय सदन के जरिए देशवासियों को कहना चाहता हूँ, खासतौर से विश्व हिन्दू परिषद के लोगों से, भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, कि आप रामराज बनाने की बात कीजिए, यह रामराज, जिसको मौलाना आजाद का भी समर्थन था, जिसको मौलाना शौकत अली और मौलाना मोहम्मद अली की हिमायत हासिल थी। आप रामराज बनाने की बात कीजिए, राम-मंदिर बनाने की बात मत कीजिए। रामराज होगा तो हर हिंदुस्तानी के दिल में एक राम-मंदिर होगा, हर हिंदुस्तानी के दिल में मर्यादा पुरूषोतम राम होंगे। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो सबसे बड़ी दिक्कत है, वह यह है कि इस देश के अंदर इंसाफ नहीं है। चाहे वह गुजरात हो, चाहे पोटा का दुरुपयोग हो, चाहे उत्तर प्रदेश में जुल्म की आंधी हो, इस मुल्क में इंसाफ नहीं मिल रहा है। गुजरात में हम दो मापदंड इस्तेमाल कर रहे हैं। गोधरा में जो हुआ, वह शर्मनाक था, उसकी किसी ने हिमायत नहीं की, कोई यह कहने की हिम्मत नहीं कर सकता कि हम इस देश के अंदर दोबारा गोधरा करेंगे। गोधरा का ऐक्सपेरिमेंट करने की जो बात करेगा, हम उसके हाथ तोड़ देंगे। लेकिन इस देश के अंदर एक बार नहीं, बार-बार यह कहा जाता है कि दोबारा गुजरात होगा, बार-बार गुजरात होगा, हर राज्य में गुजरात होगा। आप यह कहकर किसको डरा रहे हैं? गोधरा के लिए आप पोटा लगाते हैं, 151 लोगों पर पोटा लगाकर आप उन्हें बंद कर देते हैं। ठीक करते हैं आप। लेकिन क्या होगा उन हजारों लोगों का, जो तीन हजार से ज्यादा लोग मारे गए, उनका क्या होगा? औरतों के पेट काटकर उनके बच्चों को निकालकर मारा गया, लेकिन उनके लिए कोई गिरफ्तारी नहीं है ! आप क्या कर रहे हैं, किस चीज के बीज बो रहे हैं? मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में आतंकवाद के बीज बोए जा रहे हैं या नहीं? जिस देश में कानून के दो मापदंड होंगे, वहां पर आप आतंकवाद से नहीं लड़ सकते और अगर कोई यह समझता है कि पोटा को बनाकर आतंकवाद से लड़ा जा सकता है, पोटा की तलवार से आतंकवाद को रोका जा सकता है, तो मुझे कहने दीजिए बहुत ऐहतराम के साथ कि दुनिया में कभी इस तरह के कानूनों से कोई आतंकवाद नहीं रुका है। पोटा की कोख से आतंकवाद जन्मेगा। यह हमने टाडा के साथ भी देखा है और आज पोटा के साथ भी देख रहे हैं। पोटा के बारे में इस सदन में जो कहा गया था कि इसका दुरुपयोग होगा, वह दुरुपयोग आज हो रहा है। मैं कहना चाहता हूं, मैं दरख्वास्त करता हूं कि मैं इस हक में नहीं हूं कि किसी प्रवीन तोगड़िया पर पोटा लगे, किसी के ऊपर पोटा नहीं लगना चाहिए, पोटा वापिस लिया जाना चाहिए। पोटा हमारी गलती थी और हमें मानना चाहिए कि हमने गलती की थी, जिस तरह टाडा के द्वारा हमने गलती की थी। पोटा के द्वारा हम इस देश को एक नहीं रख सकते, बचाकर नहीं चल सकते। मैं तो यह कहना चाहूंगा, उपसभाध्यक्ष जी, कि :-

निसार मैं तेरी गलियो के, ऐ वतन के जहां
चली है रस्म के कोई न सर उठा के चले,
जो कोई चाहने वाला, तवाफ़ को निकले
नजर चुरा के चले, जिस्मो जां बचा के चले
बने हैं ऐहले हवस, मुद्दई भी मुंसिफ भी
किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें

और यह याद रखिए कि :-

अगर आज औज पर है तला-ए-रकीब तो क्या
ये चार दिन की खुदाई तो कोई बात नही

इस चार दिन की खुदाई से अगर आप समझते हैं कि आपकी बहुत देर चलने वाली है, तो नहीं चलने वाली। पोटा को आप वापिस ले लीजिए। पोटा हिन्दुस्तान के हित में नहीं है, पोटा राजनीति के हित में नहीं है, पोटा समाज के हित में नही है। उत्तर प्रदेश के अंदर, सर, आज जो जुल्म है, अंग्रेज के राज में भी कभी इस तरह के जुल्म नहीं हुए होंगे, जैसे जुल्म आज उत्तर प्रदेश मे हो रहे हैं। एक इमरजेंसी लगी हुई है, आतंक है, वहां पर माया का आतंक है, वहां पर पोटा का आतंक है। किसी पार्टी के, कांग्रेस के दफ्तर में घुसकर कभी अंग्रेज के द्वारा गोली नहीं चलाई गई, कभी वहां आंसू गैस के गोले नही मारे गए। लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर हालत यह है कि आप सब का गला घोट रहे हैं। आप 80 साल के लोगों को पकड़कर बंद कर रहे हैं। कानून का और पोटा का आप मज़ाक उड़ा रहे हैं। आप कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तो तुम बहुत अच्छे हो, तुम्हें सौ खून माफ़ हैं, तुम कितने भी बड़े कातिल हो, तुम्हें हम मंत्री बना देंगे लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो तुम कितने भी बेगुनाह हो, तुम्हें पोटा में बंद कर दिया जाएगा। यह अगर हम लेकर चलेंगे तो हम जंगल का राज पैदा करने वाले हैं और आज उत्तर प्रदेश में जंगल का राज है। इसके लिए हमे इस स्थिति से निकलना होगा और खास तौर से उत्तर प्रदेश में हमें देखना होगा कि इसका खात्मा कैसे हो और किस तरह से वहां जम्हूरियत का जो गला घोटा जा रहा, उसे घोंटना बंद किया जाए।

इस अभिभाषण मे कहा गया है कि पिछले तीस बरस में 550 करोड़ रुपए पुलिस के माडर्नाइजेशन के लिए दिए गए थे और अब हजार करोड़ रुपए साल के दिए जाएंगे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप अदालतों के माडर्नाइजेशन के लिए क्या कर रहे हैं? मैंने इंसाफ की जब बात कही थी तो कहा था कि जिस समाज में इंसाफ नहीं है, वह सभ्य समाज नहीं है, वहां पर हक का समाज नहीं है और आप पुलिस के द्वारा इंसाफ नहीं ला सकते। पुलिस को आप माडर्नाइज़ कर लीजिए, कोर्ट्स को आप मोडर्नाइज़ नहीं कर रहे हैं। मेरे जो साथी अदालतों में जाते हैं वे जानते हैं कि कूड़ेदानों से बदतर हालत वहां आपने बना रखी है। आप तीस हजारी में चले जाइए, वहां जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं और इससे जाहिर होता है कि हम अदालतों को क्या हैसियत देते हैं और अदालतों के बारे में हमारी क्या राय है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, हमे पुलिस के साथ-साथ अदालतों को भी माडर्न करना होगा ताकि लोगों को इंसाफ मिल सके।

हम शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के बगैर न्याय नही हो सकता। शिक्षा चाहिए। शिक्षा के लिए कहा गया है कि जो एडल्ट एजुकेशन का कार्यक्रम है, सर्व-शिक्षा कार्यक्रम है, उसके लिए 5,500 करोड़ रुपए रखे गए हैं। मैं इसको वैलकम करता हूं लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि शिक्षा के इस अभियान में क्या आपने उर्दू को भी कोई जगह दी है? क्या उर्दू इस मुल्क की 14 जुबानों में नहीं है? क्या यह सेंसस के मुताबिक हिंदुस्तान मे दूसरे नंबर की जुबान नहीं है? क्या यह पूरे हिंदुस्तान को जोड़ने वाली जुबान नहीं है जो तमिलनाडु से लेकर कश्मीर तक बोली जाती है? आप एडल्ट एजुकेशन में उर्दू नहीं पढ़ा रहे हैं। सर्व-शिक्षा अभियान मे आपने उर्दू के लिए अलग से कोई हिस्सा नहीं रखा है। ऐसा क्यों है? उसके बाद आप कहते हो कि तुम मदरसे में जाते हो। मैं नहीं चाहता और मेरे लोग भी नहीं चाहते कि हम अपने बच्चों को मदरसे मे भेजें। वे भी चाहते हैं कि उनका बेटा डॉक्टर बने, वे भी चाहते हैं कि उनका बेटा इंजीनियर बने, वे भी चाहते हैं कि उनके बच्चे मॉडर्न ऐज मे कंप्यूटर साईंस पढ़ें लेकिन वे मजबूर हैं क्योंकि आपने उनसे उनकी जुबान छीन ली है और जुबान छीनने का मतलब है कि उनके रिवायात, उनकी तारीख, उनकी तहज़ीब, उनका सब कुछ आप छीन लेना चाहते हैं। जुबान छीन लेने के बाद आप कहते हैं कि ये बेजुबान हैं, इनकी जुबान काटकर फेंक दो। उसके बाद आप हम पर इलजाम लगाते हैं कि हम मदरसे मे जाते हैं, हम अपने बच्चो को मदरसे मे भेजते हैं, हम नए ज़माने के साथ चलना नहीं चाहते हैं। हम नए ज़माने के साथ चलना चाहते हैं लेकिन आप पहले हमें हमारी जुबान दीजिए। आप आज के स्कूलों मे हमारी जुबान दीजिए। आप उर्दू जुबान को उसकी जगह दीजिए। फिर आप देखेंगे कि लोग मदरसों में कम जाएंगे।

आप मदरसों को भी माडर्नाइज कीजिए। आप मदरसो में आज की शिक्षा दीजिए, कंप्यूटर एजुकेशन दीजिए। यह जो 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान है, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि आप इसके अंदर उर्दू के लिए कुछ प्रावधान कीजिए। केवल उर्दू की मुहब्बत में नहीं, बल्कि हिंदुस्तान की खातिर, हिंदुस्तान को बचाने की खातिर, आप यह व्यवस्था अवश्य कीजिए। ऐसा करके आप समाज के एक वर्ग को यह अहसास दिलाएंगे कि तुम भी हिंदुस्तान का अहम हिस्सा हो। अगर हम ईमानदारी से हिंदुस्तान में परिवर्तन चाहते हैं तो हमे इन लोगो को इनका हक देना होगा।

महोदय, बंगलादेशियों के सवाल पर मैं यह कहना चाहता हूं कि यह एक जरिया बन गया है मुल्क में लोगों को खौफज़दा करने का। बंगलादेशियों को हरगिज़ हिंदुस्तान में आने की इजाज़त नही मिलनी चाहिए! पाकिस्तानियो को यहां रहने की इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। लेकिन इस सदन मे भी मैंने सुना और बाहर भी लोग बताते रहते हैं कि हमारे यहां 2 करोड़ बंगलादेशी हैं। कोई बताता है कि 4 करोड़ बंगलादेशी हैं। कोई बताता है कि डेढ़ करोड़ बंगलादेशी हैं। बंगलादेशी हर राज्य मे बताए जाते हैं। मैं इस सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आखिर यह कब तक चलेगा? आप इस बारे मे एक राष्ट्रीय सर्वे कराइए। क्या सर्वे नही हो सकता? आप सर्वे कराइए कि कितने बंगलादेशी हमारे देश मे हैं क्योंकि आप बंगाली बोलने वालों को, जो कि एक विशेष धर्म के हैं, उनको आप बंगलादेशी कहकर निकाल देना चाहते हो? बंगाल की एक-चौथाई पापुलेशन मुसलमान है और वह बंगाली बोलती है। उन्हे गर्व है अपने बंगाली होने पर। आसाम की एक-तिहाई पापुलेशन बंगाली है। उन्हे गर्व है अपने बंगाली होने पर और मुसलमान होने पर। इसी तरह त्रिपुरा के अंदर मुसलमान लोग हैं जो बंगाली बोलते हैं। जब वे दिल्ली में काम करने के लिए आते है, मजदूरी करने के लिए आते है तो क्या उनका हक नहीं है?

3.00 p.m.

बिहार से आने वालों का हक है, देश के सारे हिस्सों से आने वालों का हक है लेकिन अगर बंगाल से आने वाला मुसलमान दिल्ली या मुंबई में अपना हक मांगता है तो आप उसे विदेशी कहकर निकाल देना चाहते हैं। आप उसे बंगला देश में धकेल देना चाहते हैं। यह बरदाश्त नहीं होगा। इसके लिए कुछ सिस्टम बनाइए। हम यह नहीं कहते कि आप बंगला देश के लोगों को यहां आने दीजिए, बिल्कुल मत आने दीजिए। आप उसके लिए सख्त कदम उठाइए। लेकिन हो यह रहा है कि आज नैतिक हथियार के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जाता है। अब तो यह हाल हो गया है कि चाहे वह बंगाली बोलता हो या न बोलता हो, जो मुसलमान औरत साड़ी बांधती है, सिंदूर लगाती है, हिंदुस्तान की परंपराओं पर चलती है, हिंदुस्तान की वेशभूषा पहनती है, उसको आप बंगलादेशी कहकर निकाल देना चाहते हैं। उसको आप बंगला देश भेज देना चाहते हैं। यानी मुसलमान के लिए भी आपने लिबास बना दिया है कि सलवार-कमीज पहनो। मेरे सामने ऐसे कितने ही केसेज आए हैं दिल्ली के अंदर भी जहां कहते हैं कि तू कहां से मुसलमान है? तू तो साड़ी बांधती है, तू तो सिंदूर लगाती है, मतलब यह कि तू बंगला देश से आई है। मैं जानता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान औरत शादी होने पर सिंदूर लगाती है। अगर यह सिंदूर नहीं लगाती है तो उसे शादीशुदा नहीं माना जाता। मेरी परंपरा, मेरी ज़मीन, मेरी मिट्टी, हिंदुस्तान है। आप मुझसे मेरी परंपरा छीन लेना चाहते हैं? आप जिन्ना के रास्ते पर चल रहे हैं। आप जिन्ना की परंपरा को हिंदुस्तान में चलाना चाहते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह ठीक नहीं है, यह गलत है। इसके खिलाफ हमें लड़ना होगा। इसके खिलाफ हमें उठना होगा।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात इस शेर के साथ खत्म करता हूं कि -

"हम परवरिश-ए लौह कलम करते रहेंगे।
जो दिल पे गुज़रती है रकम करते रहेंगे।
एक तर्ज़े तगाफुल है सो उनको मुबारक।
एक अर्ज़े तमन्ना है सो हम करते रहेंगे"।

मैं इनसे यह भी कहूंगा कि -

"अजब दौरे हवादीस अब शहरे सियासत में।
हमें लाशें तो मिलती हैं मगर कातिल नहीं मिलता।
लेगा ज़माना खून का हर बूंद का हिसाब।
कातिल को कत्ले-आम से थकने तो दीजिए "।

बहुत-बहुत शुक्रिया।

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : सिद्दिकी साहब, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपने मेडन स्पीच की परंपरा का मान रखा और बिना मेरे घंटी बजाए आपने अपनी बात खत्म कर दी। माननीय एच.के. जयारे गौडा जी यहां उपस्थित नहीं हैं। माननीय राजीव रंजन जी आप बोलिए।

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" (बिहार) : उपसभाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के माध्यम से पूरे वर्ष में सरकार की जो नीति होती है उसको देश की जनता के सामने रखने का काम सरकार करती है और आज हम महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा कर रहे हैं। महोदय, हमारा देश समस्याओं से घिरा देश है और कई ऐसी समस्याएं हैं जिससे आज पूरा देश जूझ रहा है। लेकिन समस्याएं होना स्वाभाविक है, यह एक स्वाभाविक परिक्रमा है लेकिन समस्याओं के निराकरण के लिए जब हम अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं तथा उन प्राथमिकताओं के तय करने में दृष्टि में कहीं दोष होता है तो उसका असर पूरे देश पर पड़ता है और जो हमारी मूल समस्याएं हैं वे किनारे हो जाती हैं और जो कोई महत्वहीन समस्याएं हैं वे ऊपर चली आती हैं। आज महोदय, हमारे देश के सामने बेरोजगारी, भुखमरी, कृषि जैसी समस्याएं हैं। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारी पूरी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है। लेकिन अगर आज सबसे बदतर स्थिति है पूरे देश में तो वह किसानों की है और किसी की नहीं है। आज हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता अयोध्या हो गई है। महोदय, यह बड़ी दुखद स्थिति है। चाहे वह सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सत्ता पक्ष की भी कई पार्टियां है, आज अयोध्या का सवाल हमारे देश की प्रमुख समस्या हो गई है और पूरे देश में चर्चा का विषय हो गया है। महोदय, पूरा सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस बात पर सहमत हैं कि अयोध्या का विवाद या तो आपसी बातचीत से तय होना चाहिए या फिर अदालत के फैसले के अनुसार तय होना चाहिए। मामला अदालत में है, बातचीत कहीं हो नहीं रही है। लेकिन फिर पूरे देश में यह समस्या बनी हुई है। इसको सीधे तौर पर अदालत पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन अदालत के पास जब यह विचाराधीन है और हम अदालत के पास जाते हैं यह कहने के लिए कि अविवादित जमीन को छोड़ दिया जाए मंदिर निर्माण के लिए तो फिर हम एक नया विवाद पैदा करते हैं। इसलिए महोदय, जो हमारी प्रमुख समस्याएं हैं देश के सामने उन समस्याओं से ध्यान हटाकर हम अति महत्वहीन विषय की ओर पूरे देश का ध्यान आकृष्ट किए हुए हैं। महोदय, हम लोगों के यहां पुरानी कहावत भी है कि -"भूखे भजन न हो गोपाला।" आज इस देश की ऐसी बड़ी आबादी है जिसके तन पर वस्त्र नहीं है, पेट में भोजन नहीं है और पूरे देश में भगवान का जाप हो रहा है। तो इसलिए महोदय, आज जरूरत इस बात की है कि जो हमारे देश की मूल समस्याएं हैं उन पर ध्यान केन्द्रित किया जाए और उनके निराकरण का उपाय किया जाए, बाद में फिर जो समस्याएं हैं उनको देखा जाए। महोदय, आज जो हमारे देश के सामने सबसे बड़ी समस्या है यह है बेरोजगारी की समस्या। आज हमारे देश मे जो बेरोजगारी की दर है वह बढ़ती ही जा रही है। आज की तारीख में जो पूरी आबादी है उस पूरी आबादी मे जो रोजगार के योग्य लोग हैं वे करीब-करीब 50 करोड़ हैं। 50 करोड़ लोगों में 40 करोड़ लोगों को रोजगार प्राप्त है। लेकिन उन 40 करोड़ में से भी तीन करोड़ ऐसे हैं जिनको साल में मात्र 180 दिन अर्थात 6 महीना ही रोजगार मिलता है। 6 महीना वे बैठे रहते हैं। तो आज स्थिति यह है कि पहले से 10 करोड़ लोग हमारे यहां बेरोजगार हैं और प्रति वर्ष 75 लाख नए लोग बेरोजगारी की पंक्ति में आ रहे हैं जो रोजगार की तलाश में आ रहे हैं। यह संख्या बराबर बढ़ती चली जा रही है। अगर हमारी यही स्थिति रही तो इस पर हम नियंत्रण नहीं कर पायेंगे और आने वाले समय में हमारे देश में बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा होने वाली है।

महोदय, यह ठीक बात है कि हम सबको सरकारी सेवा मे नहीं लगा सकते हैं, हम सबके लिए नौकरी की व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो स्वरोजगार की व्यवस्था है, उसकी व्यवस्था हम कर सकते हैं। उसके लिए हमारे देश के जो परम्परागत उद्योग हैं, उन पर हमको

ध्यान देना पड़ेगा। कृषि हमारे देश का परम्परागत उद्योग है, मत्स्यपालन हमारे देश का परम्परागत उद्योग है, पशुपालन हमारे देश का परम्परागत उद्योग है। ये हमारे देश के परम्परागत उद्योग हैं, इसलिए हमको इन क्षेत्रों पर केन्द्रित होना पड़ेगी तभी हम बेरोजगारी को काबू में कर सकते हैं, नियंत्रण मे कर सकते हैं।

महोदय, कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जिससे 77 प्रतिशत लोग जुड़े हुए हैं। लेकिन स्थिति यह है कि 1950-51 में जीडीपी में जो सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें कृषि का योगदान 97 परसेंट था और आज वह घटकर 24 परसेंट हो गया है। इससे स्पष्ट होता है कि हम अपने कृषि उद्योग को कहां पर ले जा रहे हैं? हमको आज अपने को कृषि पर केन्द्रित करना पड़ेगा। अगर कृषि का भट्ठा किसी ने बैठाया है तो वह कांग्रेस है। जब से कांग्रेस ने डब्ल्यु.टी.ओ. और गैट का समझौता किया है तब से कृषि का भट्ठा बैठा है। इंटरनेशनल मार्केट में आज हम कम्पीट नहीं कर सकते हैं। कम्पीट इसलिए नहीं कर सकते हैं। ...**(व्यवधान)** ..

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहता हूं। डब्ल्यु.टी.ओ.का जो फाइनल डिसीज़न हुआ है वह तो आपके टाइम मे ही हुआ है। आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। आपने इसको करेक्ट क्यों नहीं किया? ...**(व्यवधान)**...

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : आपने दस्तखत कर दिए थे इसलिए हम क्या कर सकते थे?

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : उसका हर साल रिवीज़न होता है। ...**(व्यवधान)**...

श्री के. रहमान खान (कर्णाटक) : उसमें फाइनल सिग्नेचर किसने किए हैं? ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रेमचन्द गुप्ता : अभी अरुण जेटली जी टोकियो में गये थे। He did not raise any of these issues there.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : हां, ठीक कह रहे हैं। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : उपसभाध्यक्ष जी, उनकी गलतियों का सुधार हो रहा है। ...**(व्यवधान)**... आप तो देवगोड़ा जी की सरकार में थे, उस समय क्यों नहीं कर रहे थे। उस समय लालू जी टमाटर और कद्दू पर भाषण करते थे। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : आप बैठ जाइये। आप आसन ग्रहण करिए। इस बात को 'ललन' जी भी जानते हैं। आप उनको बोलने दीजिए।

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : आज हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में टिक नहीं पा रहे हैं। जो यूरोपीय देश हैं वहां पर किसानों को सबसिडी दी जाती है। यहां पर करीब-करीब 300 बिलियन डालर की उनको सबसिडी दी जा रही है। अमेरिका में 30 हजार डालर की सबसिडी

किसानो को दी जा रही है और अभी हाल ही मे हमने एक अखबार मे पढा कि एक बिल पास करके अमेरिका ने यह फैसला किया है कि अगले दस वर्षो तक वह 180 मिलियन डालर और सबसिडी अपने किसानो को देने की व्यवस्था करेगा। जितनी सबसिडी यूरोप के देश और अमेरिका अपने किसानो को दे रहे हैं, उतनी सबसिडी आज हम अपने किसानो को नहीं दे रहे हैं, इसीलिए हमारी उत्पादन लागत बढ़ रही है और उत्पादन कम हो रहा है। ऐसी स्थिति मे आज हम अन्तर्राष्ट्रीय मार्केट मे कम्पीट करने की स्थिति मे नही हैं। ...**(व्यवधान)**...

महोदय, हमारे देश मे उत्पादन लागत मे लगातार वृद्धि हो रही है। हमारे देश मे वर्ष 1998-99 मे जो गेहूं के उत्पादन का खर्च था, वह 481.37 रुपये था और जो बढ़कर 2000-01 मे 580.75 रुपये हो गया है। हमारे उत्पादन की दर वही है। हमारे यहां धान की उत्पादन लागत 595 रुपये से बढ़कर आज 705 रुपये हो गयी है। आज हमारे यहां प्रति हैक्टेयर उत्पादन लागत पर खर्च बढ़ रहा है। लेकिन विश्व मे गेहूं की उत्पादन लागत 1997-98 मे 13.7 सैंट प्रति किलोग्राम थी, जो आज घटकर 09.05 रुपये हो गयी है। धान मे उत्पादन लागत 1997-98 मे 44 सेंट था जो आज घटकर 33 सैंट हो गयी है। महोदय, विश्व मे एक तरफ उत्पादन लागत घट रही है और हमारे यहां उत्पादन लागत बढ़ रही है। इस पर अगर हम नियंत्रण नही पाएंगे तो हम कैसे कंपीट कर पाएंगे?

महोदय, इसके अतिरिक्त आज कृषि के जो उत्पाद हैं, उनका आयात बढ़ा है। 1990-91 मे हमारा जो टोटल आयात था, उसमे कृषि उत्पाद से संबंधित जो आयात था, वह मात्र तीन परसेंट था। आज यह बढ़कर सात परसेंट हो गया है। अब आयात के कारण भी हमारी पूरी कृषि प्रभावित हो रही है। महोदय, हमारी जो मूल समस्या है बेरोज़गारी, वह कृषि पर आधारित है और अगर हम अपने पारम्परिक उद्योगो को इम्प्रूव नही करेंगे, उनमे सुधार नही लाएंगे तो हम बेरोज़गारी पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। यदि हम बेरोज़गारी पर नियंत्रण नही पाएंगे तो हमारी जो अन्य समस्याएं हैं, उन पर नियंत्रण पाना मुश्किल होगा। जनरल शंकर राय चौधरी इंटरनल सिक्यौरिटी की बात कर रहे थे। आज बेरोज़गारी के साथ देश की आंतरिक सुरक्षा भी जुड़ी हुई है। अगर बेरोज़गारी दूर नहीं होगी तो देश में आतंकवाद बढ़ेगा। इसलिए बेरोज़गारी के साथ हमारी सारी समस्याएं जुड़ी हैं, इसलिए आज सरकार को पूरे तौर पर बेरोज़गारी पर केंद्रित होना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRI RAM JETHMALANI (Maharashtra): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am conscious of the fact that there is a very little time at my disposal. Though I have moved about 25 amendments to the Motion, I propose to concentrate only on five topics, and I will devote only a few minutes to each one of them.

Sir, some of the speeches that have been made on this Motion have, doubtless, been characterised by a great heat and passion, and I must give a compliment to my friend, Shri Lalu Prasadji, that his speech contained a lot of passion, heat, and bluster. But, I must say that behind all that bluster, there was a solid core of sense and sensibility which the

House, and, particularly, the Government, will ignore at their own peril; it contained some words of advice which do call for introspection, thinking and action.

Sir, out of the five topics, the one which assumes a great importance, every time a crucial step in the evolution of Indian democracy comes along, is, doubtless, the topic of Ayodhya. Even the President has found it of sufficient importance to mention it in his speech. He has devoted a paragraph, paragraph 15 of his speech to Ayodhya. But I must say, Sir, that I am deeply, deeply disappointed about that paragraph and its contents. What it says, in substance, is that 'either settle it by agreement or settle it by a judicial decision.' Sir, these are not the only two alternatives of settling this problem. This is a problem which is a threat to the unity and integrity of the country. If it is a threat to the unity and integrity of the country, it requires much more serious thought than by casually saying that the courts will decide this matter, if you do not settle it by agreement amongst yourself. If an agreement can be brought about, it is well and good, but an agreement which has eluded us for the last half-a-century will not come about in the next few days; and, it is a disgrace to our legal system that the title suit has been pending for the last 50 years. It must be a record in the history of judiciary in any country that a suit should be pending for 50 years, and, today it is only in the court of the original jurisdiction. After this suit is decided, - and, I assure you it won't be decided for the next 10 years - there will be an appeal, and, probably, a second appeal, and so on. At least, in the life-time of all of us here, probably, this litigation will never come to an end. What is the net result? The net result is that the gulf that divides the two communities will continue to widen, and national integration shall be the most tragic casualty of the pendency of either this litigation or this lack of agreement. Sir, I want to say something which certainly will not bring any pleasure to my friends on this side, nor will I win any particular number of friends on the other side. I do wish to say this that, today, my Hindu friends do believe that they are the majority community. Doubtless, they are. They believe that they have the monopoly of love for this country. Let us assume that both these claims are right. Then, we must remind ourselves of that famous story of the two women who fought for the custody of a child before a *Quazi*. They could not agree, and the *Quazi* wanted to partition the child. Ultimately, the real mother had to say, "I do not want the child to be killed, let the other one take it." If the claim is that you love the country, the sacrifice must come from here. I have believed, and I have said it more than once before,

that the way of solving the problem is that the majority community must announce that until and unless non-Hindus lovingly, with a feeling of reverence, come and participate in the building up of this temple, the temple shall not be built. If you make this kind of a historic announcement that only when every single Muslim recognises that Ram was the Imam-e-Hind as Iqbal called Him.

SHRI SHAHID SIDDIQUI: We have already said that Rama is *Maryada Puroshottam* and Imam...

SHRI RAM JETHMALANI: When they lovingly say that we come to build this temple; we want it to be built, then, Sir, it will be the greatest glory of Hinduism; it will be the greatest success of national integration. Maybe that it may not evoke that kind of a response which I am expecting from the Muslim community, but, at least, national integration would have been saved in the process; maybe that the temple will remain un-built for an indefinite length of time. Sir, it is time that we realised that if we talk of secularism and we are proud of secularism, secularism means the subordination of religion to region except in those areas where region with humility admits its own defeat and says that these are problems which 'I cannot solve'. Then, you go to religion by all means. But, primarily, it is region alone which shall prevail in a secular society, and I believe that region and commonsense and the good of the nation require that this controversy must be ended and the only way of ending it is the one that I have very respectfully and in all humility suggested.

Sir, the second topic to which I wish to devote some attention is the POTA. The POTA has been criticised. Sir, I was a great critic of TADA, and I remember, Sir, still, making a very long speech on TADA - attacking it and attacking its continuance. I was very happy that the TADA was ultimately allowed to expire. But when the POTA came, I supported it. I supported the POTA even though it was a reincarnation of TADA. I supported it because I have found that the Security Council, by a Resolution passed on the 28th of September, 2001, had called upon all Member-States to enact a legislation to outlaw terrorism and the United States had given a lead by introducing a new law on their Statute Book called the Patriot Act. The POTA is a copy of the Patriot Act, and it is also a copy of the Anti-Terrorism Act, which Britain passed a few days before. Sir, I supported it. But, we all were promised in this House that POTA would not be misused. Sir, I do not want to go into illustrations of its misuse. Looking around, the

most tragic illustration of the misuse of POTA is my friend, Vaiko, who has been detained. I cannot understand how anybody in his senses can justify the imposition of POTA on that poor gentleman who has been our colleague in Parliament. Sir, what distresses me more is the statement which the Home Minister made the other day. I have great respect for my friend, Shri L.K. Advani. He is a very, very dear friend of mine. I must confess But coming from a friend, the distress is more. He said the other day in this House that POTA is a law and order problem of States and the Centre is not concerned. Sir, there are two fatal errors in this argument. The first fatal error is that the constitutional validity of POTA was sustained on the ground that it does not deal with public order, which is a State subject, but, it deals with the Defence of India. If it was a subject, where public order is the pith and substance of that Act, then only the State Legislatures are competent to enact the law, this law would be invalid. But, the Supreme Court saved it by saying that it relates to the Defence of India, and the Defence of India surely is a Central subject, I don't think that the Home Minister was right in jettisoning his constitutional responsibility.

Secondly, even if it was relating to a State subject, it must, at least, be in the Concurrent List, before the Centre can legislate on it. But, it is a Central law, and there is Article 256 of the Constitution of India, which says that it shall not only be the duty, but also the right of the Central Government to see, how laws made by the Centre, are being executed in the States, and for that purpose, it has the constitutional power to issue directions, which are binding upon the State Governments. Sir, non-compliance with the law, includes misuse of that law, and therefore, I believe that, this Government is under a constitutional obligation to see that POTA is not misused in any part of the country, and if it is, in fact, misused, that must be brought to the notice of this House, and the House must enforce, what is called the Parliamentary responsibility.

Sir, the third topic on which I wish to devote a few minutes, is our judicial and legal system. Even that has found a place in the President's Address. In paragraph 15, the President has dealt with our legal system. But, I regret to say that in paragraph 15, the President only talks of one disease of the legal system, that is, law's delays. Law's delays are, of course, scandalous in this country. The Ayodhya suit, which has been pending for more than 50 years, is itself a scandalous illustration of law's delays. The Railway Minister, Shri Lalit Narayan Mishra, was killed in a bomb blast in Samastipur, and the trial in that case is still pending in the

Session's Court, and the statements of the accused are being recorded now, whereas, a period of more than 27 years has already gone by. Anybody can be shocked to see this state of affairs. But, Sir, laws delay's are not the only problem. I regret to say that no attention has been paid to the corruption, which has now crept into the Judiciary. The head of the Judiciary - not one head, but more than three heads of the Judiciary, of the judicial family - have publicly said that 20 per cent of the higher judiciary is corrupt. I want to know what the Government is doing about this corruption. Once the corruption has spread into the temple of justice, the rule of law is a myth, democracy is a myth, everything is a myth, and you must surrender to anarchy and chaos. Something has got to be done. Sir, when I talk about the judicial corruption, I am not unmindful of the fact that, compared perhaps, to some other departments of our public life, the judges are still good, and I am also not unmindful of the fact that there are some honest judges, who live a life of honourable poverty, and who continue to administer justice, in spite of the handicaps and the troubles which they face. But, Sir, something has got to be done. *(Time-bell)*. Kindly pardon me, Sir. I would like to utter just three more sentences on this particular topic. The age of retirement of High Court judges today is 62 years. It must be raised to 65 years. This creates an unseemly struggle among the High Court Judges to ascend to the Supreme Court Bench. If their age is kept at the same level, there will be no such unseemly scramble, which today goes on in the corridors of power, where the High Court Judges dance in attendance on the Law Minister, and the Law Minister trying to influence the appointment of High Court Judges. Sir, what is more, The difference between the salaries of Supreme Court Judges and High Court Judges must be brought down to such a level that there is almost a nominal difference between the two so that it is a kind of token difference, and nobody will aspire thereafter to become a Supreme Court judge, and the judicial independence will be safeguarded. And, Sir, what we find today is that - and it is again a distressing fact - we all pay lip-service to Dr. B. R. Ambedkar, and coming from Maharashtra, I am a great student and worshipper of Mahatma Phule. But I want to know what has happened to the representation of our Scheduled Castes, Scheduled Tribes and Backward Classes in the Judiciary. Sir, figures have been given that whereas on their population ratio, they should have about 610 Judges belonging to these communities, there are only 10; ten against 610! This is a scandalous state of affairs and it ought to be remedied. And the best suggestion that I can make is that when you create the National Judicial

Commission, the Scheduled Castes and Tribes, and the Backward Classes must be represented adequately on that Commission, so that one person sitting there to represent their interests will see to it that proper appointments are made. And, Sir, this theory, this argument of merit, is the biggest fraud. This whole country has been governed by the higher castes for the last 50 years; this country is in a mess. So, how do you blame the weaker sections of the society for being inferior to others in any sense? This must be remedied as soon as possible.

Sir, I now come to the last topic to which my friend, Shri Fali S. Nariman had once spoken about, supporting me. Sir, today, the greatest suffering of the world comes from serious offences against humanity - genocide, religious squabbles which lead to murder and mayhem and widespread breach of human rights. And everybody has a reason for the last one hundred years, why you need a supra-national authority for the purpose of punishing these trans-border crimes, which govern the whole world. Sir, in the 1990s, the United Nations called a Conference and it was resolved in Rome that an International Criminal Court will be created, and I found that throughout the proceedings in Rome, our representatives from India had first strenuously opposed the creation of this Court. When ultimately the Rome Conference accepted this proposal, we gave a very funny reason. We said that we are not accepting it because possession of nuclear arms should become an offence, which could be tried by this Court, forgetting that only the previous year, we ourselves had atom bombs and nuclear bombs in our possession. This is the wooden-headedness of the Government and the Ministry of External Affairs. My friend, Shri Fali S. Nariman, raised that point. We were told on the floor of this House that the Minister will discuss this problem with all of us who had talked about the International Criminal Court. Nothing was done; nothing has been done. And I find from newspaper reports that they have now said that an International Court cannot be created because some day, some Indians might have to be tried there. What does it matter? If Indians commit offences of genocide, they ought to be tried there, in that Court. Sir, something has got to be done.

Lastly, Sir, my friend's welcome presence here does invite me to say a word about Kashmir. Sir, only the other day, as the result of persistent questioning, an announcement was made on the floor of this House that some ex-bureaucrat, Shri Vohra, has been appointed as the Government's interlocutor. We welcome this appointment; it is a very

belated step, it is an insignificant step, but it is nevertheless, a step for which one would give credit to the Government, which slept over this very important matter for so long. But Sir, this appointment raises more questions than it answers, and I regret that the President's Address gives no particular clue to these answers -- did or did not the Government think of the Vohra mission only after Mufti's Press Club outburst ten days ago? He came here and said that you are talking to the Nagas, but you are not talking to the people of Kashmir. After that complaint was made, they thought about this Vohra business. On the day of the President's Address, obviously, Shri Vohra had not been thought of. They gave that reply only on the 18th, when this question was raised. Then, what are the exact terms of reference and the parameters of Shri Vohra's job? Who are the persons with whom he is required to confabulate? In what order and where is he to open and continue this dialogue?

Is there any time frame fixed for completion of this job? What are the options for an honourable solution to the problems which are open for discussion, and what are those which have been expressly pre-empted? Who will decide whether a particular individual, group or section eschewed the path of violence? Sir, the People's Democratic Front and the Hurriat have publicly eschewed violence. Has Mr. Vohra been asked to talk to these two Groups? Has the Government briefed Mr. Vohra on the conflicting statements made, from time to time, about the desirability of talks with these two Groups? Sir, is the Government aware of an article which appeared in the name of Mr. I.D. Swami, Minister of State for Home Affairs, in *the Hindustan Times* of 19th January, under the title "The Hurriat missed the bus." In that, it is emphatically said that there will be no talk. Sir, these are some of the questions which were answered not in the evasive manner in which the main question was answered on the 18th. But, if genuinely answered, some more questions will arise. I hope, Sir, the Kashmir problem will receive the kind of attention that it deserves.

Sir, one last line. Never in the history of India, never in the history of this dispute, has there been a more propitious moment for solving this problem. Pakistan, today, is weak; its international friends have deserted it. They are only supporting it for the sake of supporting, because they still need it. And, Sir, when the enemy is weak, it is not an occasion for arrogance, it is not an occasion for hopping in joy, but it is an occasion for statesmanship and striking, because, now, the iron is hot and we must go forward and solve this problem which is becoming a cancer for the whole of this country. Thank you.

उपसभाध्यक्ष (श्री रमा शंकर कौशिक) : श्री एम.वी. राजशेखरन, आपके 8 मिनट हैं। कृपया 8 मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिएगा।

SHRI M.V. RAJASEKHARAN (Karnataka): Sir, I am very much conscious of the time of our party, and I will try to conclude my speech within that time.

[THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY) in the Chair].

Sir, respected President, while addressing the Joint Session, has drawn our attention to the "Vision 2020", and has also drawn our attention to the Tenth Plan. He has spoken about the people's plan and the people's participation. Sir, as you are aware, Gandhiji had always said that any plan made in our country should be people-oriented. Now, in this context, I would like to draw the attention of this House towards the plan made by this Government. Is the plan made people-oriented? Is it implemented by this Government? The Government is leading at the behest of the VHP and the Sangh Parivar which are taking the country on the path of destruction and disappointment. Sir, none of the things mentioned in the President's Address is people-oriented. I have got the greatest respect for our President who is one of the proud sons of this great country, but, unfortunately, the Government has tried its best to put some of their ideas through the mouth of the President, and it is here that I am very greatly concerned. The President has listed many things during his Address. He has spoken about the urban and rural programmes to mitigate poverty, but he has not stated the road map, and how that is going to be achieved within the given time.

Sir, the President has also spoken about urban amenities that are going to be created in the rural areas. In this context, he has mentioned four very important principles on which they would be created. He has spoken about Physical Connectivity. Yes, it is needed. But how will it happen? It means we need to build rural roads and provide rural infrastructure in almost every village. Our villages are being connected with the big cities.

Where are the funds for this? Have they got the right map drawn up? How are they going to achieve this? Sir, the President has also spoken about electric connectivity. That means we need to provide electricity to almost every village in this country. Have they got a vision

about that? How are they going to do it? Where are the plans? Have they already taken the needed steps to achieve and move in that direction?

Sir, the President has also spoken about knowledge connectivity. Yes, Sir, it is needed. Today, the whole world is moving based on knowledge. But, what are we doing in this country? If we want to have the knowledge connectivity, our present educational system has to be taken to a level of excellence where every one of our boys and girls should be able to get the best education. Do we have the infrastructure? Do we have the needed schools? Do we have all the things which we expect to get it done? How are they going to do it?

Sir, then, the President has also spoken about marketing connectivity. Sir, if you take the rural scene, it is in shambles. Our farmers, who are toiling day and night, who are producing food articles, are not able to sell them. They have to walk miles and miles to catch a bus and take their products to the bigger markets. How are they going to create these markets? Sir, this needs, in a massive scale, godowns to stock the food products and other things which they are producing. We need cold storages; we need transport facilities. Has it been realised that how this is going to be done by this Government? Sir, mere talk is not going to bring results. The saying is that if wishes were horses, beggars could ride. This is the situation which we are facing. Sir, again, as I said, this requires massive investment. From where will we get funds? Just today morning, our hon. Finance Minister was telling that he is not able to get the required investment from the foreign resources. The bureaucracy is one of the biggest hurdles. He was talking about red-tapism; he was talking about procedural delays. How is he going to get and from where will he get the money? Sir, the point is that unless they are going to give utmost attention to this, this would remain as a big dream.

Sir, regarding agriculture, we have been reading in newspapers almost everyday, every month and every year, hundreds of farmers are committing suicide. Has he gone into the details in this regard? Has he found out the reason? Our farmers are toiling day and night. They are producing the wealth which this country requires. Today, Sir, if there is any political stability in this country, it is because of the farming community putting in their hard work and making the food available in the market. Sir, we have seen, in Indonesia, food was not available for a few weeks. A great revolution took place and the President Mr. Suharto, who was the

most powerful President, was thrown out. Sir, the Soviet Union, one of the super-powers, got disintegrated because of non-availability of food. We must remember these things. These are the things which we need to keep always in our mind and make the planning and see that the plan delivers the goods to the people for whom it is meant. Sir, this Government, I must say, basically lacks vision and direction, which is so much needed for speedier growth and all-round development. Sir, NDA Government is consisting of more than two dozen parties pulling apart. So, how do they expect to deliver the goods? This is the question, which, through you, I would like to ask this Government.

In recent times, there is a growing trend of communalisation. All of us are very seriously concerned about it. Our society, which stood for tolerance, peace and harmony for generations, is being divided on communal lines. The VHP, the Bajarang Dal and the Sangh Parivar are spearheading the hate campaign, with the result the future of our country is in danger. *(Time-bell.)* I will just conclude, Sir. I will take another two minutes and conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): You have already taken eight minutes.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: This point has to be realised by this Government and the unity and integrity of this country has to be maintained. The most important thing that should be kept in view is the good of all people.

Sir, as you are aware, our basic heritage, our basic concept, is "सर्वे जना सुखिना भवन्तु". It is the concept which this great country has given to the entire world. We have also spoken that it is the good of all which is at the heart of everybody in this country, and this has to be kept in mind.

Another point to which I would like to draw the attention of the House, through you, Sir, is that today we have a foreign exchange reserve of more than 80 billion dollars. We have got 60 million tonnes of foodgrains. How did it happen? It did not happen all of a sudden, within three or four years. It happened because of the hard work put in by the previous Congress Government. It was the Congress Government which laid the foundation for the growth of this country. Therefore, let us not allow this Government just to fritter away the wealth which we have got and see to it that it is utilised for the development of this country.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): You have to kindly conclude now.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: Sir, I am just concluding. I don't want to go into the disinvestment issue. Everybody knows about it. But they have to take into consideration the social security of the labour class. I hope this Government would take it into consideration.

Another point is that this country is rich in cottage industries and small-scale industries. Today, they are in a shambles. How is this Government going to revive those industries? These are industries which are giving employment to millions of people. These people are today being threatened about their livelihood. How is this Government going to set these things right?

I would just mention one or two points and conclude. I would like to draw the attention of this House to corruption. During this Government's rule corruption has reached the highest point. Sir, as you read in the newspapers, according to one study, which has been published, as far as corruption is concerned, the international rating of India is that it occupies the 69th position in the world. It is a shame to us. I would like to know how this Government is going to contain corruption. There is no mention about it in the Address. The former President, Shri K.R. Narayanan, while addressing the Golden Jubilee Celebrations, on August 15, 1997, said and I quote.....

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Now, you have to conclude. There are ten more speakers.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: I am just concluding, Sir. I want to say one more thing on foreign affairs, though my colleagues and leaders have already spoken. After quoting what he has stated, I will take one minute on foreign relation and conclude.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): Now you have to conclude your speech.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: He said, "It seems that people have to be at the forefront of the fight against corruption, communalism, casteism and criminalisation of politics". I would like to plead with everyone who is working in this Government to take care of this point.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P. PRABHAKAR REDDY): You have taken a long time. You have to conclude now.

SHRI M.V. RAJASEKHARAN: I am concluding, Sir. Just one minute. As far as the Foreign Policy is concerned, many of our leaders have already spoken and I do not want to go into those details. Unfortunately, we have always looked towards the West, forgetting about the East. Sir, towards the East, we have got our cultural relationship. I would plead with the Government that they must take this fact into consideration and give the highest priorities as far as promoting trade, commerce and cultural relationship with all the countries in the East including Japan, are concerned.

Lastly, Sir, as far as South-Asia is concerned, unfortunately, we do not have good relations with all the countries. It is the utmost thing in our interest that we should promote good relations with all the South-Asian countries and we must develop good relations with both China and Russia. Thank you very much.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P.PRABHAKAR REDDY): Mr. Manoj Bhattacharya, you have five minutes.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, the time allotted was actually 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P.PRABHAKAR REDDY): No, I have been told this is the time allotted. Ten more Members are there to speak.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I would like to conclude in the time specified. However, I will try. To my mind, Sir, it is a compendium of annual reports of different departments of the Government of India written in a monotonous and drab manner without even literary beauty. It is practically a type of election speech that has been made for reading by the hon. President of this country. Sir, perhaps this has been written by different bureaucrats who have no commitment to the nation, as a whole or to the vast number of poor people of this country. It is a common knowledge that the hon. President does not write the speech himself. The speech is written by the Cabinet.

Sir, I have one suggestion. On the 17th, we had witnessed - you had also experienced it - that our hon. Vice-President, Chairman of this House, virtually collapsed while reading this monotonous, lengthy and drab speech having no content, no policy directions. So, Sir, my strong suggestion is that this bilingual system of reading the speech should be abandoned forthwith.

Sir, in this long address, there is virtually no mention about the employment opportunities or the unemployment problem of this country. You will also appreciate that this has assumed a horrifying proportion. The official estimates, the Government, says it is nearly 12 crores of young people, who could produce wealth for this country, have been rendered unemployed at the moment. And, the promise made, the electoral pledge by this Government - the Government of National Democratic Alliance - was to provide one crore of jobs every year. In fact, many other hon. Members have also referred to instead of creating job opportunities, they have seen to it by their policy measures that the people have lost their jobs. Sir, in fact, on the path of globalisation, which is being vigorously followed by this Government, during the last decade of the 20th century, the number of people living in abject poverty has increased by more than 100 million whereas the world's income has been increased by 2.5% annually. India has unfortunately a major share in such anomalous situation of the entire world. I am really surprised and pained to see that there is no mention about the UN Human Development Report in this entire speech. The UN Human Development report indicates that India is positioned as 124th country, which is a shame on our part. We should have mentioned it. The Government should have had the courage to mention it and suggest the measures to ameliorate such problems. Sir, the assets of the world's three richest persons - Bill Gates, Warren Buffet and Paul Allen exceeded the combined GDP of the poorest 48 countries and the richest 225 persons are richer than the poorest 2.5 billion people across the developing world. This is the net gain of the neo-liberal globalisation which this present Government is following so vigorously. The present form of capitalist globalisation also has been seen, needless to mention, to be urban-centric, more so, in total neglect of the rural development. Whatever is being done is full of rhetorics and the political demagogy is being given credence.

Unfortunately, the President's Address has really failed to mention the atrocities that are being perpetuated on women and the weaker sections of the society. Many Members have already talked about the minorities. So

I do not want to repeat it, even though I am with them. Women have been attacked and atrocities have been perpetuated on women of all castes and all religions. The root-cause is the utter change in the cultural values of this country, ethos of this country. This Government boasts of culture and nationalism. I am sorry to say that a foreign TV channel, *i.e.*, MTV which is an American channel, has made a mockery of the image of the Father of the Nation, who is also recognised as the Father of the Nation, though reluctantly by the present Government. His image has been outraged. Not the slightest protest is there from this Government. The Government has failed to protest against it because that channel is owned by an American company. I do not know where Mr. Singhal had gone. Why didn't he raise his voice? Why didn't he protest? Where was national *Asmita*? They talk of national Asmita, Asmita of the nation. Where were they when Mahatma Gandhi's image was being outraged by an American channel? They did not protest because it was an American channel. They could not protest because they are afraid of the American domination in the world.

SHRI B.P. SINGHAL: Sir, he has taken my name. I would like to say that the VHP has protested against America...

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, I have not taken the name of Shri B.P. Singhal. There are many Singhals. I have not taken his name.

I would like to raise some more points. This is a BJP led Government. They are making a huge propaganda out of the Bangladeshi infiltrators. My friend has also referred to it. In fact, it is fundamentally ill-conceived and based on *prejudice* to whip up communal passion against the minorities. Admittedly, a significant number of Bangladeshis have migrated to India and some of them, of course, illegally. Some time back Shri L.K. Advani said, - I do not know how responsibly he said it, without having any background, without having any concrete evidence, any empirical evidence, without having any statistics, without having any survey - 15 to 20 million Bangladeshis are there. They are not infiltrators. They are mostly economic refugees. They have migrated for their own livelihood, for survival, from the poorest of the countries to a slightly less poor country. I think this number of Bangladeshi infiltrators is not correct. If at all this number is accepted as spelt out by Shri L.K. Advani, who is responsible for that? The BSF is responsible for it. The security agencies which are controlled by the Home Ministry are responsible. They are responsible for this sort of infiltration. In fact, these issues are being raked up only to

promote and serve the purpose of the extreme Rightwing fascistic communal politics, where a community is being indicated. When you accept that 15 to 20 million Bangladeshis are there, 11,250 Pakistanis are there who are essentially terrorists, you should tender your resignation as the Home Minister because you have failed to control it. You are trying to rake up communal passion in this country of ours to divide the country further. Threatening the internal security of this country. Sir, I am sorry to say that this sort of provocative statements must be stopped. This sort of provocative statements will only lead to further problems and accentuate the problem of communalism in this country of ours. This nation will be destined to its doom unless these sorts of activities are stopped. And, I must say, Sir, that I am extremely sorry to say that ..*(time-bell)*.. I am just concluding, Sir. This is my last point. I was under the impression that I have been allocated 15 minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI P.PRABHAKAR REDDY): Though I told you that you have been allocated five minutes, I have already given you ten minutes.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA: Sir, you must also be noticing that there is a tidal wave of protests throughout the world, right from Antarctica to the ice land; there is a tidal wave of protests against the war designs of the hegemonic West, particularly the United States of America and the United Kingdom. Bush and Blair - they are designing to thrust a war, unjust war, on Iraq. Sir, our Government, through this long speech of the President of India, has failed to clear its position, in so far as war designs of American imperialists are concerned. It has failed to say that we are not going to allow our land, sea and sky for any sort of war activities of this imperialist America. We have failed to say what we should do; we are only saying what others should do. Shri Atal Bihari Vajpayee, the hon. Prime Minister of this country, has only said that what others should do. He has never said what India should do, that India should take a position; India should take a lead of the G-77 countries; India should take a lead of the peace movement in this world; India should take a lead in opposing the imperialism and capitalism in this world, which is the root cause of this sort of war in the days to come.

Sir, since the time is not at my disposal, I am not going to other socio-economic aspects. I am sure that even Dr. L.M.Singhvi, my learned colleague, has tried to defend this President's Address and move the

4.00 p.m.

Motion of Thanks for this speech of the President. I am sorry that he has tried to defend something that is indefensible, and I am opposing this Motion. With these words, I conclude. Thank you, Sir.

SHRI H.K.JAVARE GOWDA (Karnataka): Thank you, Vice-Chairman, Sir. This is the fifth year in the House that I am reading the President's Address. What we have learnt in the past five years is changing the names, and a little bit of figures,. Any progress in any field is not forthcoming. I thank the President for having addressed the Joint Session of the Parliament. Even though he is the Constitutional head, he has no option but to read out the policy of the present Government. Many speakers spoke on various issues. I am going to confine myself to the issues of agriculture, employment and education.

Now, 70 per cent of the population depends upon agriculture. More than 14 States in the country are suffering from drought. There is no work for the common people. Cattle are suffering without fodder, but President's Address contains only the schemes which are on paper. They have not been given effect to. The main contention of the Government is that there are no sufficient funds. As there are no sufficient funds, they are not able to provide drought relief programmes, but they try to pass on the responsibility to the State Governments. Almost all the State Governments in the country are in a financial crisis. They are not in a position to undertake relief work programmes. Under these circumstances, what I would like to say is that agriculturists, farmers and agricultural coolies are the worst affected people during the regime of the NDA Government. They have not made any sincere effort to redress the problems faced by the agriculturists. This is one of the areas that the NDA Government has to review their policy and take concrete steps to solve the problems, particularly the drought-affected people. The second aspect of the matter is where 70 per cent of the cultivated area is depending on monsoon. But there is no concentrated effort by this Government excepting merely to say that they are going to make a policy. But they only appointed a chairman for interlinking the major rivers in the country. But, even if this is done, it is going to take another 30 years,, and by that time, the present farmers would not be there to reap the fruit of the linkage of rivers.

The second point that I want to make is that the President's Address does not contain a word about suicides being committed by the farmers all over the country. This is one of the burning issues among the people, particularly, the farmers. In order to save their honour and prestige, the farmers, who are in severe debt, have committed suicide. No word has been said in the President's Address about these farmers, and there is apathy on the part of the Government towards them. I feel that this Government is doing a great injustice to the farmers.

The next point I would like to say is regarding unemployment. Unemployment is one of the worst enemies of the country. Now, it is a well-known fact all over the country that there are no job opportunities for even the educated youth. This is the result of the mistake that has been committed by various Governments in power, including this Government. Because of their bad policies and bad administration, after independence, public undertakings have been disinvested, and job opportunities have been curtailed. Now the private institutions are not in a position to provide jobs. There is no future for the younger generation, the educated youth, of our country. Under these circumstances, I urge upon the Government to come out with a policy of providing jobs to the millions and millions of unemployed, untrained and unskilled workers, in our country.

Sir, the next aspect is regarding education. Now, education has become a private industry. Even though it is the policy of the Government to provide free education up to 14 years, but what is happening in reality? Sir, I am saying this with great concern. The decision of the Supreme Court Bench on T.A. Pai's case is a devastating judgement in the history of the Indian education system. Now, I will give you one example. In Karnataka, which is the most progressive State in the matter of education, after the judgement by the 11-member bench of the Supreme Court, the entire infrastructure has been destroyed. Prior to the Judgement of the Supreme Court, it was only on the basis of merit that seats were given to students, whether they were belonging to backward classes, minorities or meritorious students, including the sons of farmers. Now, after the judgement of the Supreme Court, it is only the money, and not merit, which is deciding the fate of the students in Karnataka and the entire country. It is a matter to be looked into by the Legislatures of the States as well as Parliament. We have to amend the Constitution. Otherwise, in the name of judgement and law, it would become a weapon in the hands of the private institutions to collect and grab money as they like and dislike. Sir, prior to the Judgement

of the Supreme Court, a student was given a seat based on his merit or on the basis of his minority status or backwardness. But, now, to get an engineering seat, he has to pay Rs.5-10 lakhs, and to get admission into a MBBS course, he has to pay Rs.20-25 lakhs. This Judgement has, in a way, helped private institutions to grab money from the people. I, therefore, request the Prime Minister and the Legislature of all the States to bring about an amendment in the Constitution, and what was prevailing prior to the judgement of the Supreme Court has to be restored. Otherwise, this would lead to anarchy and it will cause an irreparable loss and will be a great injustice done to the nation. This is a point to be taken into consideration. I hope the NDA Government would come forward to rectify the mistake committed by the Supreme Court.

Mr. Vice-Chairman, Sir, so far as the Kelkar Committee's Report is concerned, I do concede that the country will not progress without adequate resources at its command. The Kelkar Report has recommended that agricultural income should be taxed. I think, it is not proper. It is very wrong. I want to make it clear, Sir, that the cost of agricultural inputs and the returns are not at all comparable. The farmers are living from hand to mouth. They are not in a position to earn even Rs.5,000/ per month. Under these circumstances, the Government should not at all think of imposing a tax on the agricultural income.

So far as the health sector is concerned, the Government has formulated several policies and programmes. But, what is the real position, so far as health sector is concerned? Take the Government hospitals in rural areas, or towns, where generally the poor people go for treatment. What do you find? Medicines are not available in Government hospitals. There is no proper treatment there. Care should be taken tc see that we have a proper health policy, and that proper health care and medicines are made available for the needy people.

MR. VICE-CHAIRMAN (SHRI P.PRABHAKAR REDDY): Please, conclude, Mr. Gowda.

SHRI H.K. JAVARE GOWDA : So far as the issue of corruption is concerned, even the legislators now-a-days are not seriously talking about it. Corruption has become so rampant in India as if it is running in the blood of most of us, Indians. You take the allocation and utilisation of resources for any programme, whether it is Plan expenditure or Non-Plan expenditure, you find corruption everywhere; 30-40 per cent of the

resources are misappropriated. How are we going to achieve the targets that are envisaged in the Plans? The President's Address has not at all touched upon the issue of corruption. I strongly feel, Sir, that unless corruption is tackled in an effective way and the corrupt are punished adequately, it will not help in the proper execution of our development projects and, ultimately, we will not be able to progress.

Mr. Vice-Chairman, Sir, we have been deviating from our path; of late, we have been taking up issues that are not related to progress and development. What are our priorities? Our priorities should be to help the farmers, to give employment, to provide health care and so on. In stead of that, what are we doing? We are raising the issues of *Ram Mandir, Hindutva* and so on, which are not relevant to the progress of our country. What I would like to say here very strongly is that the 'ancillaries' of the BJP -- I want to call them the BJP's ancilliaries -- the VHP and the Bajrang Dal, are openly raising extraneous issues at the behest of the BJP and diverting the attention of the people. Therefore, I urge upon the Government to look into the problems of the poor farmers and take necessary steps to ensure their welfare. I hope this Government will come to the rescue of the farmers. Thank you, Sir.

श्री परमेश्वर कुमार अग्रवाला (झारखंड) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर डा. लक्ष्मीमल्ल सिंघवी द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताय रखा गया है, मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

उपसभाध्यक्ष जी, इस अभिभाषण मे विगत वर्षों की विभिन्न क्षेत्रों में की गई उपलब्धि तथा भविष्य की योजनाओं का दिग्दर्शन देखने को मिलता है। मैं राष्ट्रपति जी के इस सुझाव का खुले दिल से स्वागत करता हूं कि अयोध्या विवाद या तो दोनों समुदायों के बीच वार्ता द्वारा या न्यायपालिका के निर्णय द्वारा सुलझाया जाए। राष्ट्र हित में अच्छा होता यदि यह विवाद आपसी बातचीत से सुलझाया जाता। राष्ट्र की बहुत सी ऊर्जा, संसद के माननीय सदस्यों का बहुत सा समय, इस विवाद के विभिन्न पहलुओ पर अपना-अपना पक्ष रखने में व्यर्थ ही गंवाया जाता रहा है। मैं भारतीय मूल की कल्पना चावला एवं उसके साथियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होने मानव समाज के सुनहरी भविष्य के लिए खोजी यॉन में अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। ये लोग मनुष्य पीढ़ी के हृदय मे नक्षत्र के समान सदा ही विद्यमान रहेंगे। मैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को बधाई देता हूं जिन्होंने विधान सभा के चुनाव में बुलेट का जवाब बैलट से दिया। साथ ही हमारी सशस्त्र सेनाओ, अर्द्ध सैनिक बलो, पुलिस बलों की कर्त्तव्यपरायणता के लिए भी अभिनंदन करता हूं और उन सभी के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने राष्ट्र की बलिवेदी पर अपने प्राणो को न्योछावर कर दिया।

राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के पैरा 4 के संबंध मे विपक्षी दलो ने आरोप लगाया है कि पंचवर्षीय योजना का मसौदा महज एक चुनावी घोषणा-पत्र है। इस संबंध मे मैं यह कहना चाहूंगा कि विपक्ष के द्वारा लगाया गया आरोप बिल्कुल निराधार है। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण मे जिन योजनाओ का उल्लेख किया है वे दीर्घकालीन योजनाएं हैं। वोटो की दृष्टि से इन बातो का कोई महत्व नही है। परन्तु इन योजनाओ का लाभ भविष्य मे मिलने वाला है। इस सरकार के पहले भी कई सरकारें आई। उन्होने भिन्न-भिन्न क्षेत्रो मे सुधार घोषित किए, किन्तु यह पहली बार हुआ है कि जब राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रो मे घोषित सुधारो को सफल बनाने का एक राष्ट्रीय संकल्प नजर आता है। इन सुधारो के लिए राशि भी आवंटित की गई है ताकि सुधारो का कार्यान्वयन हो सके। अत: आवश्यकता इस बात की है कि सभी वर्गो के लोगों को मिल-जुल कर इन राष्ट्रीय समस्याओ के समाधान के लिए आशावादी दृष्टिकोण से आर्थिक तथा सामाजिक सुधार को करना होगा। हमे अपना योगदान भी देना होगा। आज हमारा देश आतंकवाद से ग्रसित है। पड़ोसी देश हमारे राष्ट्र में दहशत का माहौल बनाने के लिए कृतसंकल्प हैं। हमारी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आंतरिक सुरक्षा को भी पड़ोसी देशो से खतरा हो गया है। बाहरी आतंकवादी तथा आंतरिक आतंकवाद से भी निपटने के लिए सरकार ने पुलिस बलों को आधुनिक बनाने में अगले दस वर्षों मे एक हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। यह सचमुच सराहनीय निर्णय है। हमारी स्वयं की जनसंख्या एवं बाहर से आए अवैध प्रवासियों की समस्या एक गंभीर समस्या बन गई है। इसे हल करना होगा। घुसपैठ को रोकने के लिए भारत-बंगला देश सीमा पर समयबद्ध तरीके से बाड़ लगानी होगी अन्यथा यह समस्या विकराल रूप धारण करती जाएगी। विश्व के कई देशों मे पानी की समस्या को देखते हुए विशेषज्ञो का मानना है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो सकता है। भारत में सूखा एवं बाढ़ के चलते हर वर्ष जान-माल की हानि होती रहती है। यदि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक नदियो को जोड़ दिया जाए तो भारत में अतिवृष्टि तथा अनावृष्टि का खतरा सदा के लिए समाप्त हो जाएगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। आजादी के 55 साल बीतने के बाद भी नदियों को मिलाने का प्रयास कभी गंभीरता से नही हुआ। मैं आदरणीय प्रधान मंत्री जी को उनकी दूरदर्शिता के लिए बधाई देता हूं जिन्होने भारत की नदियों को आपस मे जोड़ने की परियोजना को स्वीकृति दे कर इस योजना को साकार करने के लिए कदम उठाए हैं। इस परियोजना पर 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपये की लागत आने की संभावना है। इस परियोजना के पूरा हो जाने पर पेयजल, सिंचाई, ऊर्जा तथा पर्यटन के क्षेत्र मे महत्वपूर्ण लाभ होगा। विभिन्न प्रदेशों मे विभिन्न दलों की सरकारों को क्षेत्रवाद से ऊपर उठ कर राष्ट्र हित की इस योजना, लोक हित एवं महान यज्ञ में शामिल हो कर अपने कर्त्तव्यों का वहन करना होगा। जब से जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार ने देश की बागडोर संभाली है तब से ग्रामीण क्षेत्रो की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। स्वजलधारा, जो कि पीने के पानी से संबंधित है, ग्रामो को पक्की सड़कों से जोड़ना, शिक्षा प्रसार, क्षेत्रो मे विकास, दूरगामी योजनाओं का संकल्प एवं कार्यान्वयन किया गया है, क्योकि भारत गांवो में बसता है।

उपसभाध्यक्ष महोदय, स्वर्णिम चतुर्भुज के नाम से राष्ट्रीय राजमार्ग के विकास की योजना एक क्रांतिकारी योजना है। आने वाले समय में इस योजना से राष्ट्र को कितना लाभ होगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। यह आने वाली पीढ़ी के लिए इस सरकार की एक अमूल्य देन है, जो नए तथा सुदृढ़ भारत के संकल्प को साकार करने का सही प्रयत्न है। इसी के साथ ही पुरानी पड़ गई रेल पटरियों तथा पुलों के नवीनीकरण हेतु अगले पांच सालों तक

17,000 करोड़ रुपए की एक व्यापक राशि का आवंटन किया गया है। बदलते आर्थिक परिवेश से जूझने के लिए पेट्रोलियम क्षेत्र मे, बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए बहुत से कदम सरकार द्वारा उठाए गए हैं, जिनकी मैं सराहना करता हूँ। ऊर्जा के क्षेत्र मे भी बहुत से कार्य किए गए हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अबाध गति से बढती हुई जनसंख्या हमारी बहुत सी समस्याओ का मूल कारण है। यह समस्या किसी पार्टी या किसी वर्ग विशेष की नही है या कोई यह क्षेत्रीयता से संबंधित समस्या नही है। यह समस्या राष्ट्र की समस्या है, इसलिए हम सभी भारतवासियो का दायित्व है कि इस समस्या की गंभीरता को सोचते हुए इस पर रोक लगाने का सामूहिक संकल्प करे।

उपसभाध्यक्ष महोदय, हमारे देश को आज कैन्सर, एड्स, मलेरिया, कालाजार जैसे अनेक घातक रोग घेरते जा रहे हैं। आज की युवा पीढ़ी, विशेषकर 15 से 24 वर्ष की आयु के बच्चे एड्स जैसे घातक रोग से पीड़ित हो रहे हैं। हमारे देश मे आज लगभग चार लाख लोग एचआईवी पोजिटिव के शिकार हैं। इसके मुकाबले देश के अस्पतालो मे ऐसे मरीजो के बिस्तरों की संख्या कम है, जिसमे बढ़ौतरी किए जाने की आवश्यकता है ताकि हम इस घातक रोग से लड़ सके। इन रोगों के उन्मूलन के लिए सरकार जो कदम उठा रही है, वह प्रशंसनीय हैं। कैन्सर, एड्स की औषधियां बहुत महंगी हैं। एड्स से ग्रस्त एक रोगी को अपने इलाज के लिए प्रतिमाह 9000/- रुपए खर्च करना पड़ते हैं। मेरा सुझाव है कि इन घातक रोग की दवाइयों के मूल्य पर नियंत्रण करना चाहिए और एड्स के प्रति जागरूकता हेतु लागू किए गए प्रोजेक्टों में वृद्धि करनी चाहिए। इसके साथ ही सरकारी अस्पताल, एड्स क्लीनिक खोलने के साथ साथ कौन्सलिंग सेटर भी खोलने की आवश्यकता है। मेरा निवेदन है कि ऐसे मरीजों के लिए वित्तीय सहायता का प्रावधान होना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, देश मे क्रीड़ा संबंधी साहित्य की काफी समय से मांग की जा रही है। खेलों को बढ़ावा देने के लिए युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय ने राष्ट्रीय युवा नीति का मसौदा तैयार किया है, जो प्रशंसा का विषय है। हमे अपने खिलाड़ियों का मनोबल और उत्साह बढ़ाना चाहिए ताकि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेलो में अपना बेहतर प्रदर्शन कर सके। हमें ऐसा कोई कदम नही उठाना चाहिए, जिससे हमारे खिलाड़ियों के उत्साह और मनोबल का किसी तरह से ह्रास हो। मेरा सुझाव है कि राजनीति से खेलो को अलग रखा जाए।

अंत में मैं इन सभी राष्ट्र हित की योजनाओं के लिए सरकार को बधाई देता हूँ और इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूँ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के इस धन्यवाद प्रस्ताव को एकमत से स्वीकार करें और संकल्प करे कि राष्ट्र की समस्या सबकी साझा समस्या है, इसे सुलझाने का काम भी सबको मिलकर करना है। इसी के साथ ही मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास किए जाने की आशा करता हूँ। धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : श्री हरेन्द्र सिंह मलिक। श्री डी.पी. यादव।

श्री डी.पी. यादव (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, धन्यवाद, जो आपने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर मुझे बोलने का अवसर दिया। चूंकि मेरा ताल्लुक किसान और खेती से है, इसलिए मैं अपनी बात वहीं से शुरू करना चाहूंगा क्योंकि आज पूरे मुल्क के स्तर पर किसान की दुर्दशा है।

महोदय, सरकार ने महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के द्वारा अलग अलग मुद्दों पर ध्यान आकर्षित करने का काम किया है। और अपनी उपलब्धियों में किसान की क्या प्रगति हुई है, यह भी बताया है। लेकिन मैं तो यह कहना चाहूंगा कि पिछले पांच साल के दौरान प्रगति की जगह किसान की दुर्गति हुई है और यह बात किसी से छिपी नहीं है। इसलिए हमें देखना होगा कि कृषि नीति में क्या बदलाव हुए और किसान को उनसे क्या हासिल हुआ। महोदय, मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं और उत्तर प्रदेश में आज स्थिति यह है कि यहां गन्ना किसान आत्महत्या करने पर उतारू हैं। वह किसान जिसका सारा परिवार सूरज निकलने से लेकर सूरज डूबने के बाद तक खेत में मेहनत करता है, वही किसान, जो अनाज और उत्पादन करके इस देश के भंडार को भरता है, उस किसान की आज ऐसी दुर्दशा हो रही है। उसको खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी लगातार खत्म की जा रही है, फर्टिलाइज़र उसको मिलता नहीं है, पानी इसलिए मुहैया नहीं होता क्योंकि ट्यूबवैल के लिए बिजली पर्याप्त नहीं है और उत्तर प्रदेश की हालत तो और भी अजीबो-गरीब है। हमारी केन्द्र सरकार ने पोटा का कानून बनाया है, उसका कितना सदुपयोग और दुरुपयोग हो रहा है, यह आए दिन अखबार और मीडिया के माध्यम से हम लोग लगातार पढ़ते-देखते रहते हैं। आज अगर उत्तर प्रदेश में वास्तविकता को लेकर किसी जनप्रतिनिधि ने ज़बान खोलने की कोशिश की तो मैं नहीं जानता कि उस पर कब, किस दिन पोटा लगाकर उसकी ज़बान को बंद कर दिया जाएगा। अब तो जनप्रतिनिधियों को, चुने हुए लोगों को वहां डर और भय सताने लगा है और वे उसी तरह से डर और आतंक के साये में हैं, जिस तरह से पूरे मुल्क में अल्पसंख्यक दहशत में हैं, डर और आतंक में हैं। आज आम आदमी का जनजीवन, विशेषकर उत्तर प्रदेश में, उसी तरह के दहशत के चक्कर में आ चुका है। मैं कहना चाहूंगा कि किसान और विशेषकर आज का गन्ना किसान आज बहुत परेशान है। किसान लगातार मेहनत करके अपने खेतों में गन्ना पैदा करता है, बेशक उसके पीछे मंशा यह होती है कि हमारी आर्थिक स्थिति ठीक हो, लेकिन इसके साथ ही साथ उसके पीछे यह मंशा भी होती है कि हमारे देश के लिए उत्पादन इकट्ठा हो, हम लोग कृषि क्षेत्र में आगे बढ़ें, लेकिन आज पूरे प्रदेश के अंदर स्थिति यह है कि वहां किसान को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और यह महज़ इसलिए नहीं कि मिल-मालिक किसान को उचित मूल्य नहीं देना चाहते, बल्कि मैं कहना चाहूंगा कि सिर्फ सरकार की नीति का निर्धारण गलत ढंग से होने के कारण केवल किसान को ही नहीं बल्कि मिल-मालिकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ा है। आज पूरे मुल्क में गन्ना और चीनी उद्योग संकट में है।

मान्यवर, अब मैं महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के दूसरे पहलू, जिसमें रोजगार की व्यवस्था का ज़िक्र किया गया है, के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। महोदय, रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में उन बेरोज़गार नौजवानों से मेरा वास्ता पड़ता है जो लगातार दिल्ली और सांसदों के मकानों पर रोज़गार की सिफारिश कराने के लिए आते हैं और मैं आपको यकीन से बताना चाहता

हूं कि बड़ी-बड़ी मल्टी नेशनल कम्पनियो और छोटे उद्योगो मे बंद और छंटनी के प्रभाव से आज यह स्थिति पैदा हो गई है कि नौजवानो का एक बहुत बड़ा समूह, जो रोज़गार मे लगा हुआ था, आज यह बेरोज़गार हो चुका है। यह बहुत ही चिंताजनक और गंभीर विषय है, लेकिन मैं नही जानता कि सरकार के पास इसके लिए कौन सी नीति है। मैं इस विषय में विशेषकर यह भी कहना चाहूंगा कि समाज का जो पिछड़ा और कमज़ोर वर्ग है, इस पूरे अभिभाषण को पढ़कर मैंने यह जाना कि पिछड़े वर्ग के लोगों को, जिनकी संख्या इस देश में सबसे ज्यादा है, उन करीब 65 करोड़ लोगों के बारे में कुछ सोचा ही नहीं गया है और उपेक्षा का शिकार यह वर्ग लगातार प्रताड़ित होता हुआ बेरोज़गारी की तरफ बढ़ रहा है।

मान्यवर, मैं इस अभिभाषण को सुन रहा था और जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मैंने देखा कि महामहिम राष्ट्रपति जी ने सरकार का पक्ष अभिभाषण मे रखा है। उसमें कहा गया है कि पुलिस व्यवस्था का आधुनिकीकरण किया गया है। मैं अपने साथ बीती हुई एक घटना का ज़िक्र यहां करना चाहता हूं। पिछले सत्र के दौरान एक दिन मैं नौएडा में एक टी.वी. कार्यक्रम "परख" में भाग लेने के लिए गया हुआ था। मेरे साथ दूसरे सदन के कुछ साथी भी वहां मौजूद थे। इत्तिफाक से उस दिन मेरा ड्राइवर एक वर्कशॉप से गाड़ी लेकर घर के लिए चला और तुगलक रोड थाने के पास उसकी टक्कर एक थ्री-व्हीलर से हो गई।

मान्यवर, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि मेरा ड्राइवर गाड़ी वही छोड़कर, पुलिस के डर की वजह से घर आ गया। मैंने उससे कहा कि टक्कर होने के बाद आपको पुलिस के समक्ष जाना चाहिए था और अपनी गलती बतानी चाहिए थी। उसने कहा कि पुलिस के एक इंस्पैक्टर ने उससे यह पूछा कि गाड़ी किसकी है? उसने मेरा नाम लिया। तो ड्राइवर से कहा गया कि आपको यह बयान देना है कि इस गाड़ी मे डी.पी. यादव बैठे हुए थे और इस गाड़ी को डी.पी. यादव चला रहे थे। यह पुलिस के आधुनिकीकरण का एक नमूना है। जहां की पुलिस को यह भी शऊर नही है कि एक सांसद को यह कहकर यह किसी केस मे फंसाना चाहती है जो वहां से कोसों दूर किसी ऐसी जगह मे मौजूद है जहां किसी टी.वी. चैनल का कार्यक्रम रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने यह सवाल इसलिए उठाया कि पुलिस के आधुनिकीकरण की बात यहां कही गई है।

महोदय, मैं आपको यह बात भी बता देना चाहता हूं कि उससे अगले रोज़ यहां जंतर-मंतर के पास पार्लियामेंट थाने पर जो घेराव हुआ, बिहार के कुछ सांसद और किसानों के प्रतिनिधियों पर पुलिस द्वारा लाठियां बरसाई गई और उस परिप्रेक्ष्य में वहां के डी.सी.पी. को सरकार द्वारा निलम्बित किया गया। मुझे दो रोज़ बाद यह देखकर बहुत अफसोस हुआ कि जिस डी.सी.पी. को यह कहकर कि आपने माननीय सांसदो के साथ अमानवीय व्यवहार किया है, जांच के दौरान निलम्बित किया गया था, जैसे ही सत्र समाप्त हुआ, दो रोज़ बाद, उन्हे पुनः अपनी जगह बहाल कर दिया गया। मुझे कोई ऐतराज़ नही है इस बात से लेकिन मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि ये जो मान्यताएं हैं, इन मान्यताओं की अनदेखी करने पर सरकार लगातार आमादा है। अगर आधुनिकीकरण के नाम पर पुलिस व्यवस्था ऐसे लोगो को भी प्रताड़ित करने से नहीं मानेगी, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी के साथ जो उसका व्यवहार है, जो उसका बर्ताव है, वह क्या होगा? मान्यवर, मैं आपसे क्षमा चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी.प्रभाकर रेड्डी) : आप कनक्लूड कीजिए।

श्री डी.पी.यादव : मैं हाऊस में कभी-कभी ही बोलता हूं। मुझे हर रोज लगातार हाथ ऊपर करने का शौक नहीं है। मैं इसमें किसी की अवमानना नहीं करना चाहता लेकिन आप रिकॉर्ड देख लीजिए कि हम सत्र में जब बहुत ज़रूरी समझते हैं, तभी बोलते हैं। आज महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है। इसलिए मैं पिछले सत्र और इस सत्र के दौरान बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, मैं यह कहना चाहूंगा कि कानून की दृष्टि से मैं न्यायपालिका का बेइंतहा आदर करता हूं, इज्जत करता हूं लेकिन मुझे कभी-कभी अफसोस होता है और मैं यह कहने से अपने आपको नहीं रोक पाता हूं कि पिछले महीने दिल्ली के एक स्पेशल कोर्ट द्वारा निर्देशित या आरोपित एक विशेष जाति को दोषी करार दे दिया गया। अभी माननीय जेठमलानी जी यहां फॉस्ट-ट्रैक का जिक्र कर रहे थे। वे कह रहे थे कि ललित नारायण मिश्र का बरसों पुराना बिहार का जो केस है, यह अभी तक लंबित है। न्याय की नजर में जो अब तक बहुत पहले आ जाना चाहिए था लेकिन दूसरी तरफ हमारी सरकार ने फास्ट ट्रेक कोर्ट बनाए हैं, अच्छी बात है, खुशी की बात है लेकिन कोई न्यायाधीश अगर एक प्रश्न-चिन्ह लगा दे ऐसी बहादुर जाति पर जिस जाति के लोगों ने पार्लियामेंट को बचाने के लिए अपनी जान दी हो, अक्षरधाम में बलिदान दिया हो और कारगिल के युद्ध में परमवीर चक्र प्राप्त किया हो तो निश्चित तौर से मैं अपने आपको कहने से नहीं रोक पाया कि कहीं न कहीं नीति निर्धारण में कमी है और सरकार को अपनी आंख और दिमाग खोलकर के नीति निर्धारण करने का काम करना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : अब आप कांक्लूड कीजिए, बहुत टाइम ले चुके हैं और बहुत स्पीकर भी हैं।

श्री डी.पी. यादव : मान्यवर, अभी मैंने आपसे निवेदन किया था। मैं भी उसी चुनी हुई प्रक्रिया से यहां पहुंचा हूं जिससे सब पहुंचे हैं। बेशक मेरे पीछे कोई बड़ी पार्टी न सही लेकिन अगर अपनी अभिव्यक्ति और कहने के विचार को भी नहीं रख पाए तो मैं इससे आगे कुछ नहीं कह सकता।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : नहीं, समय नहीं है। 5-6 और स्पीकर हैं।

श्री डी.पी. यादव : मान्यवर, समय दिया जा सकता है, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि समय दीजिए तथा बड़ी पार्टियों के कुछ समय को थोड़ा कर दीजिए।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : आप कांक्लूड कीजिए।

श्री डी.पी. यादव : क्योंकि यह मंदिर और मस्जिद के मुद्दे आम जनमानस को सुख देने वाले मुद्दे नहीं हैं, महज राजनीति को कायम रखने के लिए और अपने आपको राजनीति में जिंदा रखने के लिए मंदिर और मस्जिद के मुद्दों को बनाया गया है, आम आदमी का कुछ लेना-देना नहीं है। इससे हमारी धार्मिक भावनाएं जुड़ी हैं, हम मंदिर और मस्जिद में आस्था रखते हैं।

लेकिन जिस तरीके से मस्जिद और मंदिर के मुद्दे को उठाकर आज पूरे देश में साम्प्रदायिकता का तनाव बना हुआ है, उसका महज कारण सिर्फ यह हो सकता है कि लोग अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : आप कांक्लूड कीजिए, यादव जी।

श्री डी.पी. यादव : मैं अपनी एक और बात आपके सामने रखना चाहता हूं कि मीडिया एक सशक्त माध्यम है। निश्चित तौर पर इलेक्ट्रोनिक मीडिया आने के बाद यहां प्रसारण में बहुत सुधार हुआ है। लेकिन कुछ तथाकथित मीडिया जो महज विज्ञापनों के आधार पर आर्थिक धन बटोर कर अपना साम्राज्य स्थापित किए हुए हैं और हम देखते हैं कि वह अपने आपको बहुत ही तेज, बहुत ही निर्भीक, बहुत ही सच्चा बताते हैं। मान्यवर, मैं अपनी बात पर आता हूं। गुजरात में चुनाव से पहले की बात है। मेरे पास एक सुबह मीडिया के लोग मेरे घर पर पहुंचे और मुझसे कहा कि डी0पी0 यादव जी, हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। हमने कहा किस विषय में? उन्होने कहा कि परसो आपकी गाड़ी एक थ्री व्हीलर से टकरा गई है। हमने कहा -हां, टकरा गई, क्या बात हुई? उन्होंने कहा कि इसमें आपका इंटरव्यू चाहिए। मान्यवर, मुझे हैरत हुई। मैंने उन पांच लोगो से पूछा जो कंधे पर केमरा रखे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि क्या आपके मीडिया के पास इससे जरूरी मुद्दा और कोई नहीं है जबकि आज पूरे देश मे तनाव की स्थिति है। कोई और मुद्दा आपके पास नहीं है जिस पर आप अपना कीमती समय उस पर लगा सकें। मैं सिर्फ यह बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां मीडिया की स्थिति भी यह हो गई हो वहां हमारी सरकार को यह जरूर देखना चाहिए कि मीडिया बेशक उसके पक्ष में प्रचार कर रहा हो, हो सकता है उसकी अपनी बात कह रहा हो लेकिन सवाल इस देश के सवा सौ करोड़ लोगों का है। मैं सौ करोड़ नही 125 करोड़ इस देश की आबादी इसलिए मानता हूं कि जनगणना जिस तरीके से हुई है मैं जानता हूं क्योंकि मैं गांव का रहने वाला हूं। मुझे पता है। वह मैं जानता हूं कि वह कितने सही तरीके से हुई है। 125 करोड़ लोगो की आस्था का सवाल है।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : आप कांक्लूड कीजिए यादव जी, बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है।

श्री डी.पी. यादव : मान्यवर, मैं एक मिनट मे अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : मैं नेक्स्ट स्पीकर को बुला रहा हूं, आप बैठ जाइए। I am calling the next speaker.

श्री डी.पी. यादव : मान्यवर, खेल और खिलाड़ी के बारे में इस अभिभाषण में कहा गया है। मेरा कहना सिर्फ यह है कि क्या सरकार कोई नीति खिलाड़ियो के बारे में निर्धारित कर पाई? आज अपने आदर्श के रूप मे जो खिलाड़ियों को नौजवान देखता है उनके आक्रोश का सामना भी खिलाड़ियों के घरों को करना पड़ा। उसका कारण, मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि अगर हमारी नीतियां सही रही होतीं तो निश्चित तौर से इस सवा सौ करोड़ के देश में ऐसे खिलाड़ी पैदा हो सकते थे, निकल सकते थे जो सारी दुनिया मे अव्वल आते। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि सिफारिश के आधार पर खिलाड़ियों का चयन किया जाता है और सही रूप मे जो खिलाड़ी है ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : आप बैठ जाइये।

श्री डी.पी. यादव : उसे आगे आने का मौका सिर्फ इसलिए नहीं दिया जाता है क्योंकि वह कमजोर और पिछड़े वर्ग का है।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : नेक्स्ट स्पीकर श्री गवई।

श्री डी.पी. यादव : उसकी सिफारिश राजनीतिक तौर पर नहीं होती है।

उपसभाध्यक्ष (श्री पी. प्रभाकर रेड्डी) : आप बैठ जाइये।

श्री डी. पी. यादव : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इन तमाम बातों को कहते हुए, अपने विचार, अपने सुझाव और अपने अनुरोध के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

SHRI R.S. GAVAI (Maharashtra): Sir, I am particularly dealing with the topic of the social justice. The President's Address mentions that it is the moral bound duty of the Government to bring the weaker sections of the society, particularly the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, in the mainstream. So far as social justice is concerned, I will deal with the reservation policy only. The Constitution of India provides many provisions for the welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I shall not waste the time of the House by reading those articles. In the direct recruitment, certain percentage of reservation has been fixed for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. About 15 per cent reservation has been provided for the Scheduled Castes, and 7.5 per cent to the Scheduled Tribes in Government of India services, State Government services, and other allied services. But, I am very sorry to mention that because of not having a stricter and sincere implementation of the reservation policy in respect of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the very purpose of reservation policy is being defeated. To strengthen my point, I want to bring to the notice of the House that there are recommendations and observations of the Joint Parliamentary Committee of the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. A panel has also been appointed by the Government, that is, the Parliamentary Panel for Law to Regulate Reservation Order. Here, I will mention the observations of the Joint Parliamentary Committee. The Committee represents the Parliament. Therefore, the views expressed by that Committee, are the views of the Parliament. I don't want to elaborate the information that I have, but as an indication, I would just like to mention that the representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Central Government

Services, as on 1st January, 1999, in Group 'A' out of the total of 93,520, the SCs constitute only 10,558, that is, 11.29 per cent; in respect of Group of 'B' services, out of the total of 1,04,093, the SCs constitute only 13,306, that is, 12.68 per cent only. So far as the Scheduled Tribes are concerned, they constitute 3.39 per cent in Group 'A' services, and 3.35 per cent in Group 'B' services.

[THE VICE-CHAIRMAN, (SHRI SURESH PACHOURI), in the Chair]

It does mean that the quantum of the percentage, laid down in the reservation policy, is not being fulfilled. The observations of the Parliamentary Committee on the Welfare of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes are there. The Committee - in its 29th Report, which was recently tabled in the Parliament - says, "There should also be a Central law to regulate the implementation of the reservation policy for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in all the State Governments, Ministries, Departments of the Government of India, Public Sector Undertakings and the private sector."

I have already mentioned that a Parliamentary Panel had made out a strong case for a Central law to regulate the implementation of reservation orders. It was a 31-member Committee headed by Shri Ratilal Kalidas Varma. The Committee, while making a case for creating a nodal Ministry to look after proper implementation of reservation orders had made these observations and I quote: "It has taken a serious view of the unfavourable attitude' of the Government for not creating a national policy of reservations for SCs and STs in the private sector and in the public sector. There is a total lack of coordination and liaisoning among the Department of Personnel and Training, the Ministry of Social Justice and Empowerment, the Ministry of Tribal Affairs and the State Governments, the Committee felt." It further observed: "The Committee was "pained" to learn that there was no Central Authority at the moment to exercise its power to ensure that the intake of SCs and STs was as per the Indian Government reservation orders. In the Committee's view, in case a doubt or dispute in regard to the implementation of reservation orders arises, instead of shifting the responsibility to one department or another, concrete and concerted efforts should be made to solve the problem." It observed that a casual approach has been adopted by the Government to abide by the Committee's earlier recommendations. "The Government does not seem to be serious towards these recommendations which is deeply disturbing and a matter of graver

concern to the Committee." The Committee further observed,"Whenever a question of implementation of reservation order arises, the concerned Ministries tried to shift their responsibilities on each others shoulders. It also recommended that the Government evolve a mandatory law for adequate representation of SCs and STs in the jobs while disinvesting any Government institution. Besides this, it should make sure that the private sector safeguards the interests of SCs and STs in jobs as was guaranteed in the Constituted."

Recently, an hon. Member had elicited information from Dr. Satya Narayan Jatiya, the hon. Minister of Social Justice and Empowerment. He wanted to know whether the Government proposes to enact legislation to provide reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the private sector companies in the changed economic scenario. In reply to this question, the hon. Minister had stated that the Government has not taken any decision in the matter of enactment of a legislation to provide reservation to Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the private sector companies.

Sir, before I conclude, I would like to point this out that the Reservation Policy for the Scheduled Castes and Scheduled Tribes is being totally neglected, and, therefore, it is being totally defeated. On a number of occasions, the Members of this House had put questions regarding this, and an assurance was given by the Government that the Reservation Policy would be properly implemented. I earnestly request the Government of India, particularly, the hon. Prime Minister, to bring out a comprehensive legislation which would deal with all the problems of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes. I request that adequate representation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, in line with the reservation policy of the Government of India, should be made. Thank you very much.

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, दिनांक 17 फरवरी, 2003 को दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में महामहिम राष्ट्रपति जी ने जो अभिभाषण दिया और जिस पर इस माननीय सदन में धन्यवाद का प्रस्ताव डा. एल.एम. सिंघवी जी ने प्रस्तुत किया, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं प्रथमतः डा. सिंघवी को उनके सारगर्भित सुन्दर भाषण के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा।

मान्यवर, महामहिम राष्ट्रपति जी ने हरियाणा के छोटे से कस्बे में जन्मी महान वैज्ञानिक कल्पना चावला की कोलम्बिया यान की 1 फरवरी की दुर्घटना में असामयिक, आकस्मिक मृत्यु पर हार्दिक दुख व्यक्त करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत सरकार ने मैटसेट

सीरिज के उपग्रहों का नामकरण कल्पना चावला करने का निर्णय किया है। मैं सरकार के इस कदम का हार्दिक स्वागत करता हूं। सरकार ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के प्रारूप को अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस योजना में सरकार ने रोजगार सृजन और सर्वसाधारण की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। जिससे देश में बेरोजगारी कम होगी और योजनाओं का लाभ सर्वसाधारण तक पहुंच सकेगा। अत: मैं सरकार के इस कदम का भी स्वागत करता हूं। इस योजना में सकल घरेलू उत्पाद की वार्षिक वृद्धि का औसत का लक्ष्य 8 प्रतिशत रखा गया है। यह महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। परन्तु समय की मांग है कि सरकार येन केन प्रकारेण इस लक्ष्य को प्राप्त करे और देश की जनता तथा सभी राजनैतिक दलों को अपने परस्पर के मतभेद भुलाकर एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करना चाहिए। उपरोक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघ तथा राज्यो को आपस में विचार-विमर्श करने की आवश्यकता है। संघ से हमारी अपील है कि वह और अधिक उदारता से राज्यो को और अधिक आर्थिक सहयोग प्रदान करे, विशेष रूप से जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं। महोदय, मैं वर्तमान सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि सरकार ने पहली बार राष्ट्र के सामने एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य "संकल्पना 2020" प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा देश को निर्धन तथा विकासशील राष्ट्र के सोपान पर से गुजरकर विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में आकर खड़ा होना है। यह कार्य इस राष्ट्र को स्वयं अपनी कूब्बत पर, अपने बल, भरोसे अपने परिश्रम, पसीने, पौरुष और पराक्रम के बल पर सम्पन्न करना है। इस राष्ट्र में एक सम्पन्न, समृद्धशाली, आत्मनिर्भर विकसित राष्ट्र बनने की सभी संभावनाएं उपलब्ध हैं। देश में प्रचुर मात्रा में जल सम्पदा है। देश में प्रचुर मात्रा मे श्रम सम्पदा है। अच्छी मात्रा मे वन सम्पदा है। केवल सामयिक संयोजन की आवश्यकता है। एक बार सामयिक संयोजन का मंत्र यदि हम सिद्ध कर ले तो दुनिया की कोई शक्ति हमे उन्नत राष्ट्र बनने से नहीं रोक सकती है। आज समय की इस महती आवश्यकता को समझते हुए इस सरकार ने "संकल्पना 2020" को सफल बनाने के लिए प्राथमिकता के आधार पर चार महत्वपूर्ण संयोजनों की व्यवस्था की है। अच्छी सड़के और परिवहन सुविधाएं, गुणवत्तायुक्त उर्जा की उपलब्धि का भौतिक संयोजन। विश्वसनीय संचार तंत्र की उपलब्धि का इलेक्ट्रानिक संयोजन। अधिक व्यवसायिक संस्थाएं व व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, उच्च गुणवत्ता युक्त संरचना वाले विद्यालय, अध्यापन के प्रति समर्पित अध्यापक, ग्रामीण दस्तकारो के लिए उत्पादन केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मनोरंजन केन्द्रों की उपलब्धि द्वारा ज्ञान संबंधी संयोजन और अंतिम संयोजन जो भारत सरकार ने प्राथमिकता पर लिया है, वह है ग्रामीण जनता को भी विपणन की सुविधा उपलब्ध कराकर ग्रामीण जनता के आर्थिक उन्नयन का संयोजन। मान्यवर, इस संबंध मे विस्तृत रूप से हमारे पूर्ववक्ताओ ने भी कहा है। मैं संक्षेप मे कहना चाहूंगा कि संघ की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने केवल अवधारणा नही पाली है, केवल कल्पना नही की है बल्कि इस दिशा में प्रयत्न भी शुरू कर दिये हैं। इसी प्रयत्न के फलस्वरूप आज पूरे देश मे पंद्रह हजार किलोमीटर लंबी, चार और छह लेन युक्त आधुनिक सड़को का निर्माण प्रारंभ हो गया है। यह 2007 तक पूर्ण हो जाना है। इससे अठारह करोड़ श्रमिक दिवसो का सृजन होगा। इसमें दस हजार पर्यवेक्षको को रोजगार मिला हुआ है। लाखों बेरोजगारों को इसमें रोजगार मिला हुआ है। इससे सीमेंट की इंडस्ट्री और स्टील की इंडस्ट्री को प्रोत्साहन मिला हुआ है। विश्वसनीय संचार तंत्र को फैलाने की दिशा मे भी इस सरकार ने महत्वपूर्ण उपलब्धि अर्जित की है। अब तक देश में केवल एक करोड़, छियासी लाख टेलीफोन कनेक्शन थे लेकिन विगत तीन वर्षों मे इस सरकार ने दो लाख, अड़सठ करोड़ और कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं। देश में अभी तक तीन लाख पी.सी.ओ.

थे, इस सरकार ने तीन साल की अवधि में आठ लाख पी.सी.ओ. उपलब्ध कराए। जहां इस देश मे केवल चौदह लाख सेलफोन थे, वहां आज इस देश में एक करोड से भी अधिक लोगों के पास सेलफोन हैं। यही नही बल्कि इस वर्ष के अंत तक अठानवे फीसदी ग्रामो तक टेलीफोन की सुविधा इस देश के लोगो को मिल जाएगी। उपसभाध्यक्ष जी, हमारे राष्ट्र को सैकडो वर्ष तक गुलामी भोगनी पड़ी है। यह एक कटु सत्य है। हम इसलिए गुलाम नही हुए कि हम कमजोर थे या कायर थे अथवा हममें आत्मसम्मान का अभाव था। हमारे देश की युवतियों ने, जब उनकी अस्मिता के लिए खतरा पैदा हुआ, उनकी आबरू के लिए खतरा पैदा हुआ, तब धधकती हुई ज्वाला मे अपने को झोककर आत्माहुति दी। इसका यह अर्थ हुआ कि इस देश मे पौरुष की कमी नही थी। इस देश मे जीवट की कमी नहीं थी परंतु यह भी कटु सत्य है कि हम फिर भी गुलाम रहे। इसका कारण सिर्फ यह था कि हमारे देश में अच्छे अस्त्र-शस्त्रों की कमी थी। यही कारण है कि अस्सी हजार की सेना वाला राणा सांगा, जो एक महान योद्धा था, दस हजार की सेना वाले बाबर से हार गया क्योंकि बाबर की सेना तोपो से सज्जित थी। यही कारण है कि लगभग एक सौ दस वर्ष तक हम अंग्रेजो के भी गुलाम रहे। क्योंकि उनके पास अच्छे किस्म के अग्नेयास्त्र थे। हमारे पास उनके मुकाबले में अच्छे अस्त्र-शस्त्र नहीं थे। मैं इस सरकार को और विशेषकर इस सरकार के नेता माननीय प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को - जिन्होने दुनिया की परवाह किए बिना 1998 मे पोखरण में परमाणु परीक्षण करके देश को एटमी-शक्ति से सज्जित किया - इसके लिए साधुवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद देना चाहता हूं। यही नही बल्कि पूर्व सरकारों के समय में पृथ्वी, अग्नि, नाग, त्रिशूल आदि जो हमारे पास प्रक्षेपास्त्र हैं, इनके परीक्षण पर जो अघोषित प्रतिबंध लगा हुआ था, इस सरकार ने उस अघोषित प्रतिबंध को हटाकर पुन: परीक्षण आरंभ किए। यही नहीं, आज हमारे पास सुपरसोनिक प्रक्षेपास्त्र ब्रह्मोस भी है, जिसे रशिया की सहायता से हमारे देश ने डेवलप किया है। इससे सारी दुनिया और पड़ोसी देश को एक स्पष्ट संदेश चला गया है कि यह सरकार राष्ट्र की एकता और अखंडता के साथ कोई समझौता नही कर सकती है, न ही समझौता करने वाली है, इसके लिए चाहे हमें कितने ही प्रतिबंध झेलने पड़े। आज हर भारतवासी गर्व के साथ कह सकता है कि अब दुनिया मे रहने वाली कोई भी शक्ति हमारे देश को गुलाम बनाने की बात सपने में भी नहीं सोच सकती है। इसके लिए हमे अपने वैज्ञानिको, इंजीनियरो और इस क्षेत्र में कार्यरत कर्मचारियों पर गर्व है। वे हमारी बधाई के पात्र हैं।

मान्यवर, इस समय अयोध्या का मसला एक बार फिर जोर पकड़ रहा है। इस देश के लोग चाहते हैं कि इसका कोई शांतिपूर्ण समाधान निकाला जाए। इस सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि समाधान या तो परस्पर वार्ता से अथवा न्यायालय के माध्यम से निकल सकता है। सरकार की इस स्पष्ट दृष्टि के लिए मैं उसे धन्यवाद देता हूं। इस समस्या के शीघ्र समाधान के लिए, इस मामले की दैनन्दिन सुनवाई के लिए न्यायालय से जो प्रार्थना की है, न्यायालय ने उसे स्वीकार भी कर लिया, मैं इस बात के लिए भी सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, वर्तमान वित्तीय वर्ष में देश को भयंकर सूखे का सामना करना पड़ा है, परन्तु संघ और राज्य सरकारो के प्रयत्न से अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाई है। माननीय उपप्रधानमंत्री की अध्यक्षता में गठित कार्य दल ने सूखा प्रभावित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सहायता उपलब्ध कराने की अनुशंसा की है। राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि के तहत अब

तक एक हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि राज्य सरकारों को दी जा चुकी है। राज्यों के आपदा राहत कोष में केन्द्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान किया है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : माननीय वर्मा जी, आपकी पार्टी से एक और वक्ता हैं। कृपया संक्षेप में बोलिए।

प्रो. रामबख्श सिंह वर्मा : जी। काम के बदले अनाज कार्यक्रम के तहत रोजगार सृजन हेतु प्रभावित राज्यों को पांच हजार करोड़ से अधिक का 50 लाख टन खाद्यान्न आवंटित किया जा चुका है। प्रभावित किसानों द्वारा लिए गए फसल ऋण का एक वर्ष का ब्याज भी स्थगित करने की सरकार ने घोषणा की है। मैं सरकार के इन प्रभावी कदमों का स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, देश में पेट्रोलियम पदार्थों के अन्वेषण कार्य में तेजी आई है और उसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए हैं। राजस्थान, गुजरात और आन्ध्र प्रदेश के कृष्णा बेसिन में पेट्रोलियम पदार्थों के विपुल भंडार मिले हैं। इससे देश की विदेशों पर आत्म-निर्भरता घटेगी और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी। देश में ब्राजील की पद्धति पर पेट्रोल में एथेनाल की 5 प्रतिशत ब्लेंडिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हुई है। पांच प्रतिशत तक एथेनाल पेट्रोल में ब्लेंडिंग करने की प्रोसैस पहले ही प्रारंभ हो चुकी है। भविष्य में यह ब्लेंडिंग 20 प्रतिशत से ले करके 25 प्रतिशत तक जाने की संभावना है। डीजल में भी एथेनाल की ब्लेंडिंग प्रारंभ होने वाली है। इससे भी विदेशों पर हमारी निर्भरता घटेगी तथा साथ ही जो देश के किसान हैं, जो गन्ना उत्पादक हैं उन्हें गन्ने का लाभकारी मूल्य भी प्राप्त होगा।

माननीय उपसभाध्यक्ष जी, इस सरकार के कार्यकाल के दौरान विदेशी मुद्रा भंडार में तेजी से वृद्धि हुई और अब 74 अरब डालर तक पहुंचने वाला है। मैं सरकार को इसके लिए बधाई देता हूं। महोदय, विश्व स्तर पर आई मंदी के बावजूद पिछले वर्ष भारत का स्थान तीव्र विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बना रहा है। इसके लिए सरकार ने जो कदम उठाए हैं उसके लिए भी मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। आज हमारा विदेशी व्यापार पिछले 9 महीने में 1 लाख 81 हजार 300 करोड़ तक पहुंच गया है। इसके लिए सरकार का कुशल प्रबन्धन जिम्मेदार है और इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, इस सरकार ने भारत की नदियों को जोड़ कर नेशनल वॉटर ग्रिड बनाने की योजना पर विचार और कार्य करना प्रारंभ कर दिया है जिस पर 5 लाख 60 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का व्यय होगा। इससे देश का सूखा और बाढ़, दोनों से इस देश के निवासियों को निजात मिलेगी। सरकार ने महत्वाकांक्षी योजना पर कार्य करना प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद देता हूं। सरकार ने किसानों की भलाई और उनकी आर्थिक स्थिति की बेहतरी के लिए संपूर्ण फसल बीमा योजना और किसान क्रेडिट कॉर्ड योजना को कार्यान्वित किया है। किसानों को लाभकारी मूल्य देने के लिए और अन्न भंडारण की समस्या को दूर करने के लिए देश से खाद्यान्नों का निर्यात इस सरकार द्वारा प्रारम्भ कर दिया गया है, जिससे 9 हजार करोड़ रुपये से अधिक विदेशी मुद्रा का भंडार हमारे देश में उपलब्ध हुआ है।

मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में आरोप लगाया है कि यह सरकार पृथकतावादी शक्तियों को बढ़ावा दे रही है। परन्तु माननीय जनरल शंकर राय चौधरी जी ने अभी अपने भाषण मे उल्लेख किया है कि एक पार्टी आईएनपीटी है। त्रिपुरा में उस पार्टी से मिल कर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। इस पार्टी के जो नेता हैं मि. विजय हैगरवाल जी उन्होंने विगत वर्ष जेनेवा मे भारत विरोधी भाषण दिया और कहा कि त्रिपुरा एक स्वतंत्र राष्ट्र है, जिसका पृथकतावादियो के साथ संबंध है। ऐसी पृथकतावादी शक्तियों के साथ कांग्रेस मिल कर चुनाव लड़ रही है। इसलिए सहजता से यह समझा जा सकता है कि पृथकतावादी शक्तियों को देश में कौन बढ़ावा दे रहा है, भा.ज.पा. दे रही है अथवा कांग्रेस दे रही है। माननीय कपिल सिब्बल जी ने कहा था कि इस सरकार को नाक के आगे का दिखाई नहीं दे रहा है। कांग्रेस की तो दूर-दृष्टि है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इसी दूर-दृष्टि के कारण कांग्रेस ने भिंडरावाला को बढ़ावा दिया था? ...(व्यवधान)...

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : वर्मा जी, एक मिनट, मुझे सदन की राय लेनी है। मैं सदन का मत जानना चाहता हूँ कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा जारी रखी जाए या सदन स्थगित किया जाए?

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal): Sir, I think, we should complete the discussion on the Motion of Thanks today. I understand that the Minister of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, has also to make a statement today. So, I would like to suggest that he can make the statement today, and we can seek clarifications, some time, later, as and when it is convenient to the Minister and to the House. But, the discussion on the Motion of Thanks should be completed today.

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है, तो अभी माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री जी पैकेज में रखे मिनरल वाटर में पेस्टीसाइड्स अवशेषों की मौजूदगी के संबंध मे अपना वक्तव्य देगे, जिस पर स्पष्टीकरण कल या बाद में पूछे जा सकते हैं। वक्तव्य के बाद राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी।

प्रो. रामबक्ष सिंह वर्मा : सर, मैं अपनी बात पहले समाप्त कर लूं।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : ठीक है, वर्मा जी के भाषण के बाद वक्तव्य होगा।

प्रो. रामबक्ष सिंह वर्मा : मान्यवर, मैं यह कहना चाहता था कि क्या इसी दूरदृष्टि के कारण कांग्रेस ने भिण्डरावाला को बढ़ावा दिया फिर ब्लू स्टार आपरेशन किया जिसके कारण बाद मे हजारो बेगुनाह सिखों की हत्या कर दी गई थी? क्या इसी दूरदृष्टि के कारण पहले लिट्टे को कांग्रेस सरकार ने बढ़ावा दिया और फिर उन्हें नियंत्रित करने के लिए अपने देश की सेना को श्रीलंका भेजा गया, जिसमें हमारों नौजवान बेवजह मारे गए? क्या इन्हीं भूलों के कारण श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या नहीं कर दी गई थी? क्या इसी दूरदृष्टि के कारण बोफोर्स तोप घोटाला कांड घटित नहीं हुआ, जिसमें वांछित इटैलियन क्वात्रोची को हम

आज तक अपने देश के कानून के हवाले नहीं कर पाए हैं? क्या इसी दूरदृष्टि के कारण कांग्रेस ने वर्ष 1948 में कश्मीर से अपनी सेना वापस बुला ली थी और तिहाई कश्मीर को गुलाम हो जाने दिया था? क्या इसी दूरदृष्टि के कारण कश्मीर जो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा नही बन गया? क्या कांग्रेस सरकार ने यू.एन.ओ. मे इस मुद्दे को पहले ले जाकर इसका विश्वव्यापीकरण नही किया?

मान्यवर, मैं कह सकता हूँ कि हां यह इस सरकार की दूरदृष्टि है और इसी दूरदृष्टि के कारण आज हम न्यूक्लीयर पावर है। हमने दुनिया की परवाह नही की, लेकिन आज इस दिशा में हम आत्म-निर्भर हैं। आज कोई भी देश हमे गुलाम बनाने की बात सोच भी नही सकता। कारगिल में हमने शानदार विजय प्राप्त की। यही नहीं बल्कि हमने संकल्पना 2020 को स्वीकार किया है, जो इसी दूरदृष्टि का परिणाम है। ऐसी अन्य और भी उपलब्धियां हैं, जिनको मैं पहले कह चुका हूँ, जिन्हें मैं दुबारा रिपीट नहीं करना चाहता। लेकिन मैं यह कहूंगा कि बांगलादेश के लोगो की अवैध प्रवेश पर कठोरता से नियंत्रण प्राप्त करना चाहिए। जो बांगलादेशी या कोई भी विदेशी अवैध तरीके से इस देश मे रह रहा है तो उसे खदेड़कर देश के बाहर कर देना चाहिए और जब तक इस देश के बाहर न खदेड़ा जा सके तब तक उसको सारे नागरिक अधिकारो से वंचित कर देना चाहिए।

उपसभाध्यक्ष जी, आज जो इराक का मामला है, इराक में आज जो युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, यह कोई लोकतंत्र का मामला नही है। ऐसा नही है कि इराक में लोकतंत्र नही है। अमरीका इसलिए उसे धमका रहा है क्योंकि इसमें उसका लालचपन है। उसका लालच यह है कि वहां जो तेल वाला भाग है उस पर कब्जा करने की उसकी नीयत है। जो काम अमरीका के राष्ट्रपति जी के पिताश्री सीनियर बुश नहीं कर पाए थे उस अधूरे काम को वह पूरा करना चाहते हैं और इसलिए आज अमरीका पूरी दुनिया को संकट मे डालने का काम कर रहा है। अमरीका को दुनिया का दरोगा बनने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। अमरीका ने हमारी सरकार से भी पूछा कि अगर इराक पर युद्ध होता है तो भारत हमे तेल भरने की सुविधा प्रदान करेगा? हमारी सरकार ने हां नही कहा है। मैं अपनी सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि अगर यू.एन.ओ. की बिना अनुमति के इराक पर अमरीकी हमला होता है तो अमरीका को तेल भरने की सुविधा प्रदान न की जाए बल्कि हम तो यहां तक कहेगे कि अगर जहां तक संभव हो उस दशा मे इराक की मदद भी करनी चाहिए।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं अपनी अंतिम बात करने जा रहा हूँ। अभी "नाम" की जो बैठक चल रही है उसमे फिर हमारे पड़ौसी दुष्ट देश ने कश्मीर के मामले को उछाला है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसका सही और मुंहतोड़ उत्तर दिया है। फिर जब दुबारा उसने बोलने का अनुरोध किया तो "नाम" आंदोलन के अध्यक्ष ने उनको फटकार दिया। मैं समझता हूँ ऐसे दुष्ट देश के लिए यही उत्तर सही था।

इन्ही शब्दो के साथ मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण का समर्थन करता हूँ और इस हाऊस में सभी राजनैतिक दलो से आए माननीय सांसदो से प्रार्थना करता हूँ कि एकमत से आप अपना समर्थन इसे प्रदान करे।

उपसभाध्यक्ष जी, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : अब माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पैकेज मे रखे मिनरल वाटर मे पेस्टीसाइड्स अवशेषो की मौजूदगी के संबंध मे अपना वक्तव्य देगे।

STATEMENT BY MINISTER

PRESENCE OF PESTICIDE RESIDUES IN PACKAGED DRINKING AND MINERAL WATER

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद यादव) : उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मौका दिया। मैं प्रणब जी का भी बहुत आभारी हूं। There has been much discussion in both Houses of Parliament...

प्रो. राम देव भंडारी (बिहार) : अंग्रेज़ी मे !

श्री शरद यादव : इसमे काफी टैक्निकल मामला है, इसलिए मैं माफी चाहता हूं। इसमे बहुत टैक्निकल वर्ड्स हैं, उन्हे हिन्दी मे बोलना तो ठीक नही था।

There has been much discussion in both Houses of Parliament and in the media on reports of pesticide residues found in samples of packaged drinking water and mineral water bearing the ISI mark. In this connection, with the permission of the hon'ble Chairman, I wish to make the following statement in this august house.

Two Indian Standards, one for Natural Mineral Water and another for Packaged Drinking Water, were formulated in 1998. These standards cover microbiological, physical and chemical safety of water.

In March 2001, Ministry of Health and Family Welfare enforced a gazette notification under the Prevention of Food Adulteration Rules, 1955, as per which Packaged Drinking Water and Mineral Water cannot be manufactured, sold or exhibited for sale without BIS Standard Mark, thereby making BIS Certification Mark mandatory. Ministry of Health is the enforcement authority and BIS is the certifying agency. BIS has so far granted more than 700 licences for packaged drinking water (including 1 in Nepal) and 6 licences for packaged natural mineral water (including one in France) to different manufacturers. The water manufactured in adherence to